



Daily

# THE PHOTON NEWS

सच के हक में...



गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं

दफोटेनन्यूज

Published from Ranchi



ऊर्जा विभाग अंतर्गत

## मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना



हर माह  
200  
यूनिट  
बिजली मुफ्त

जे.बी.वी.एन.एल से  
व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ें  
9431135503

200 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले  
उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल माफ

### मुख्य बिन्दु

- ⚡ **आर्थिक रूप से कमजोर घरेलू उपभोक्ताओं** को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- ⚡ 200 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली योजना के तहत सभी तरह के शुल्क यथा **Energy Charge, Fixed Charge, Electric Duty, FPPPA Charge** आदि की छूट 200 यूनिट तक मासिक खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को प्रदान की जाएगी।
- ⚡ यह योजना **जुलाई 2024** के बिलिंग माह से लागू की जाएगी।
- ⚡ **33,07,294** ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
- ⚡ **6,37,095** शहरी घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
- ⚡ 200 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली योजना हेतु झारखण्ड सरकार प्रतिमाह लगभग **₹350 करोड़ सब्सिडी** के रूप में झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को उपलब्ध करायेगी।
- ⚡ करीब **40 लाख** घरेलू उपभोक्ता को लाभान्वित करने का लक्ष्य।

टॉल फ्री हेल्पलाइन नंबर:

**1912/1800-123-8745/1800-345-6570**

हेमन्त सोरेन  
मुख्यमंत्री, झारखण्ड



सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड सरकार



मास्टर चाभी बरामद किये गये हैं।  
एकसूत्री चंदन कुमार सिन्हा ने  
सशस्त्र को सांवदाता सम्पलेन में  
बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि  
रामादू की ओर से कुछ अपराधी  
अपराध करने के नीयत है।  
ओरमांझी की ओर आ रहे हैं।  
सूचना के बाद टीएसपी सिल्ली के  
नेतृत्व में एक टीम का गठन किया  
गया। टीम के जुरिये सशस्त्र बला  
के साथ उकरीद मोड़ पर वाहन चेकिंग  
शुरू की गयी। इसी क्रम में रामादू  
की ओर से दो बाइक पर छह व्यक्ति  
सवार होकर आ रहे थे।





Daily

# THE PHOTON NEWS

गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं

द फोटोन न्यूज

Published from Ranchi

सच के हक में...



SHARE	
संसेक्स	: 81,183.93
निफ्टी	: 24,852.15

SARAFSA	
सोना	: 6,890
चांदी	: 90.00
(नोट : सोना 22 केरेट प्रति ग्राम)	

## BRIEF NEWS

### कांग्रेस में शामिल हो गए विनेश फोगाट व बजरंग

**RANCHI :** शुक्रवार को दिग्गज रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए। सियासी गलियारे में यह चर्चा है कि विनेश का जुलान सीट से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। बजरंग के भी चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। इससे पहले दोनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके आवास पर मिले और फिर कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। बता दें कि राज्य में एक फेज में 5 अक्टूबर को वोटिंग है। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा। कांग्रेस में शामिल होने से पहले विनेश और बजरंग ने रेले की नौकरी छोड़ दी। दोनों ओएसडी स्पोर्ट्स के पद पर थे। विनेश फोगाट ने कहा- बुरे टाइम पर पता लगता है कि साथ में कौन है।

### पूर्व प्रिंसिपल के 6 ठिकानों पर ईडी ने मारी रेड

**KOLKATA :** शुक्रवार को कोलकाता के आरजी कर मॉडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के 6 ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी। अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी के आरोपों पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर यह कार्रवाई की। इससे पहले सीबीआई इसी मामले में भ्रष्टाचार के आरोप पर घोष को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी ने सुबह घोष के बेनियाघाटा स्थित घर और उनके करीबियों के हावड़ा और सुभाषग्राम स्थित दो ठिकानों पर छापेमारी की।

### देश में 2 महीने में रेप के 149 केस आए सामने

**NEW DELHI :** कोलकाता में 9 अगस्त को टैनी डॉक्टर से रेप-मर्डर के बाद से ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच मीडिया एजेंसी ने खुद की खबरों के हवाले से देशभर में रेप केसेस की एक रिपोर्ट जारी की। यह आंकड़ा 1 जुलाई से 31 अगस्त के बीच का है। 18 साल से छोटी बच्चियों के साथ सबसे अधिक रेप केस इस रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 2 महीने में देश में 149 रेप केस दर्ज हुए हैं।

## मणिपुर में एक दिन में दो बार हमला, पहले हमले में दो इमारतें क्षतिग्रस्त उग्रवादी समूह का रॉकेट बम से अटैक, एक की मौत

AGENCY IMPHAL :

शुक्रवार को मणिपुर के विष्णुपुर में उग्रवादी समूह ने रॉकेट बम से हमला किया। इसमें 1 बुजुर्ग व्यक्ति की मौत और 1 बच्चे सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक, बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर पर धार्मिक अनुष्ठान की तैयारी कर रहा था, तभी बम गिरा। यह एक दिन में दूसरा रॉकेट बम हमला है। इसे स्थानीय लोगों ने खुद बनाया था। इससे पहले सुबह में मोहरंग से 4 किलोमीटर दूर टोंगलाओबी इलाके में रॉकेट बम गिर था। इसमें दो इमारतें क्षतिग्रस्त

### अब एंटी-ड्रोन मशीन गन का किया जाएगा इस्तेमाल, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

- मई 2023 से जारी है हिंसा
- कैदीय बलों की 198 कंपनियां मौजूद
- 17 परिवार गांव छोड़कर भागे
- अलग कुकीलैंड की मांग का सवाल



हो गई। पुलिस ने बताया कि मोहरंग में पहले कभी बंदूक और बम से हमला नहीं हुआ था। इस हमले के बाद से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई है। मणिपुर सरकार ने इन

ड्रोन अटैक की जांच करने के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने पहली बार मणिपुर में एंटी ड्रोन मीडियम मशीन गन के इस्तेमाल की

इजाजत दे दी है। यह फैसला 1-3 सितंबर के बीच राज्य में दो ड्रोन हमलों के बाद लिया गया है। राज्य में मार्च 2023 से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हिंसा चल रही है।

### पीएम नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण पर तत्काल कार्यवाही का किया आह्वान

## जल व प्रकृति संरक्षण सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा

AGENCY NEW DELHI :

शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल और प्रकृति संरक्षण भारत की सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा है। उन्होंने जल संरक्षण पर तत्काल कार्यवाही का आह्वान किया। जल से संबंधित मुद्दों के संबंध में झारखंड के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनः रीचार्ज करें और पुनः चक्रित करें के मंत्र को अपनाने पर जोर दिया। पीएम गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल के शुभारंभ पर आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण पर कहा कि जल को तभी बचाया जा सकता है, जब इसका दुरुपयोग बंद हो, खपत कम हो, जल को पुनः उपयोग हो, जल स्रोतों को पुनः रीचार्ज किया जाए और दूषित जल को पुनः चक्रित किया जाए।

### कहा- जल संरक्षण केवल नीतियों का मामला नहीं है, बल्कि सामाजिक प्रतिबद्धता भी



- सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल के शुभारंभ कार्यक्रम को किया संबोधित
- जल को तभी बचाया जा सकता है, जब बंद हो इसका दुरुपयोग

### आनेवाली पीढ़ियां करेंगी मूल्यांकन

प्रधानमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण सिर्फ नीति नहीं है, यह एक प्रयास भी है और एक गुण भी है। इसमें उबरता भी है और जिम्मेदारी भी। मोदी ने कहा, जल वह पहला मापदंड होगा, जिसके आधार पर हमारी आनेवाली पीढ़ियां हमारा मूल्यांकन करेंगी।

### भारत में केवल 4% ताजा पानी

प्रकृति और जल संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में दुनिया के ताजा पानी का केवल 4 प्रतिशत मौजूद है। उन्होंने कहा, भले ही देश में कई शानदार नदियां हैं, लेकिन बड़े भौगोलिक क्षेत्र पानी से वंचित हैं और भूजल स्तर भी तेजी से घट रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ पानी की कमी ने लोगों के जीवन पर बहुत बड़ा असर डाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण केवल नीतियों का मामला नहीं है, बल्कि सामाजिक प्रतिबद्धता का भी मामला है। उन्होंने जगरुक नागरिक, जन भागीदारी और जन आंदोलन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि

अतीत में भले हजारों करोड़ रुपये की जल-संबंधी परियोजनाएं शुरू की गई हों, लेकिन परिणाम पिछले 10 वर्षों में ही दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत नागरिकों से एक पेड़ लगाने की अपील का जिक्र करते हुए कहा कि वनरोपण से भूजल स्तर तेजी से बढ़ता है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले कुछ हफ्तों में एक पेड़ मां के नाम के तहत करोड़ों पेड़ लगाए गए हैं। मोदी ने ऐसे अभियानों और संकल्पों में जन भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की भागीदारी से जल संरक्षण के प्रयास एक जन आंदोलन में बदल रहे हैं।



**हेमंत ने पत्नी कल्पना संग फोटो शेयर कर दी हरतालिका तीज की बधाई :** शुक्रवार को हरतालिका तीज के अवसर पर राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने पत्नी कल्पना सोरेन के साथ फोटो शेयर की। हेमंत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट शेयर कर पत्नी को हरतालिका तीज की बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, हरतालिका तीज पर प्रदेश की सभी बहनों/माताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्योहार दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि आपकी जीवनसंगिनी का त्याग और समर्पण एक सुखी परिवार की नींव है।

## जम्मू-कश्मीर विस चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी 5 लाख रोजगार, हर साल 2 फ्री सिलेंडर

AGENCY SRINAGAR :

शुक्रवार को भाजपा ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि कॉलेज छात्रों को हर साल 3 हजार रुपये यातायात भत्ता दिया जाएगा। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को टेबलेट और लैपटॉप मिलेगा। उन्होंने कहा, 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे। उच्चला योजना के लाभार्थियों को हर साल 2 फ्री एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। अटल आवास योजना के जरिए भूमहीन लोगों को 5 मरला जमीन मुफ्त दी जाएगी। गृह मंत्री ने कहा- 370 हटने नहीं देंगे अमित शाह ने कहा, 'जम्मू-कश्मीर भारत का है, था और

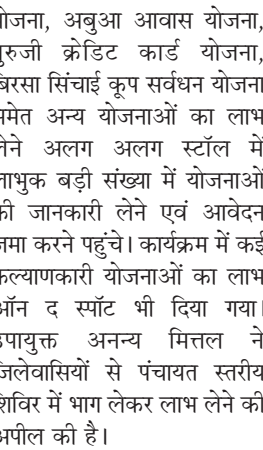
### अमित शाह बोले- कभी नहीं होगी 370 की वापसी जम्मू में बनाया जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन



रहेगा। 10 साल में राज्य का विकास हुआ है और रहा है। आज धारा 370 और 35 (ए) बोले दोर की बात बन गई है। अब ये हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। ये सब पीएम नरेंद्र मोदी के ताकतवर फैसले से हुआ। धारा 370 इतिहास बन गई है। हम इसे कभी

आने नहीं देंगे। बता दें कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटें हैं, जिनमें से 47 घाटी में और 43 जम्मू संभाग में हैं। प्रदेश में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को तीन फेज में चुनाव होने हैं। नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे।







# घरेलू विवाद में दो बच्चों का अपहरण पुलिस ने दो घंटे में करा लिया मुक्त

## छह आरोपी किए गए गिरफ्तार, बच्चे के परिवार में दहशत फैलाने के लिए किया अगवा

**AGENCY PALAMU :** पारिवारिक विवाद में भय का माहौल बनाने के लिए दो स्कूली बच्चों का अपहरण कर लिया गया। एक बच्चे को इसलिए अगवा किया गया, ताकि उससे दूसरे एवं मुख्य बच्चे का लोकेशन जानकर उसका अपहरण किया जा सके। सूचना के तुरंत बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्चे को जहां बरामद किया, वहीं 6 में से चार अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि घटना में इस्तेमाल दो मोटरसाइकिल और पांच मोबाइल फोन बरामद किया। गिरफ्तार आरोपियों में सदर थाना क्षेत्र के बड़कागांव के प्रशांत तिवारी पिता कौशल तिवारी, शहर थाना क्षेत्र के बारालोटा जनकपुरी के नीरज कुमार चन्द्रवंशी पिता राजकिशोर चन्द्रवंशी, जीएलए कॉलेज बारालोटा के कुंदन कुमार पांडे पिता नवल किशोर पांडे एवं पांकी रोड श्रीराम पथ चरकी भट्टा के वैभव भास्कर पिता विनय शुक्ला शामिल है। एसपी रीष्मा रमेशन ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया



आरोपियों व घटना की जानकारी देती एसपी रीष्मा रमेशन

● फोटोन न्यूज

कुमार चन्द्रवंशी पिता राजकिशोर चन्द्रवंशी, जीएलए कॉलेज बारालोटा के कुंदन कुमार पांडे पिता नवल किशोर पांडे एवं पांकी रोड श्रीराम पथ चरकी भट्टा के वैभव भास्कर पिता विनय शुक्ला शामिल है। एसपी रीष्मा रमेशन ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया

कि पांच सितंबर को दोपहर 3.30 बजे सूचना मिली कि बारालोटा संतजोयिवर स्कूल के 10वीं कक्षा के एक बच्चे का अपहरण कर लिया गया है। शिक्षक के सामने बच्चे को उठाने पर अपहरणकर्ताओं ने उन्हें भी चुप रहने की धमकी दी। बाइक पर

बैठाया और वहां से निकल गए। छात्र के मोबाइल फोन से दूसरे एवं मुख्य छात्र का लोकेशन पृष्ठवाया। दूसरे छात्र का लोकेशन जानने के बाद पहले वाले छात्र को जीएलए कॉलेज के पास छोड़ दिया और दूसरे को कचहरी चौक के अपहरण कर लिया। एसपी ने

**भारी मात्रा में नकली शराब बरामद, तस्कर किया गया गिरफ्तार**

**KODERMA :** जयनगर थाना अंतर्गत अवैध शराब का निर्माण एवं तस्करी किए जाने की सूचना पर पुलिस ने भारी मात्रा में नकली शराब बरामद किया। मौके से एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार किया गया है। एसपी अनुदीप सिंह ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि सूचना के आलोक में जयनगर थाना प्रभारी विकास पासवान के नेतृत्व में बीती रात थाना क्षेत्र के प्रतापपुर स्थित गोविन्द रजक 28 वर्ष, पिता शिवकुमार के घर छापामारी की गई। इस दौरान मैकडोवेल्स लमजरी स्टीकर लगा हुआ 18 पीस, मैकडोवेल्स लमजरी नंबर 1 स्टीकर लगा हुआ 23 पीस, इंपीरियल ब्लू 24 पीस, इंपीरियल ब्लू व्हिस्की 21 पीस जब्त किया गया। वहीं 6 प्लास्टिक के बड़े बोरे में शराब की खाली बोतल को भी जब्त किया गया।

## सरकारी पदाधिकारियों और कर्मचारियों की परीक्षा संपन्न

● शांतिपूर्ण माहौल में कदाचार मुक्त हुई परीक्षा : प्रमंडलीय आयुक्त

**HAZARIBAG :** केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पदद झारखंड, रांची के तत्वाधान में 2 सितंबर से शुरू राजपत्रित और अराजपत्रित पदाधिकारियों-कर्मचारियों की द्वितीय अर्धवार्षिक परीक्षा-2023 एवं प्रथम अर्धवार्षिक परीक्षा-2024 शुक्रवार को संपन्न हो गई। इस बीच उत्तरी छोटानागपुर की प्रमंडलीय आयुक्त सुमन कैथरिनी सिंगोप्रां ने समय-समय पर जिला मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय स्थित परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। आयुक्त ने प्रथम एवं द्वितीय पाली में आयोजित हो रही परीक्षा का शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त तरीके से संपन्न होने पर पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को धन्यवाद दिया।



परीक्षा केंद्र पहुंची आयुक्त

द्वितीय अर्धवार्षिक विभागीय एवं जनजातीय परीक्षा-2023 एवं प्रथम अर्धवार्षिक विभाग एवं जनजातीय भाषा-2024 के सफल संचालन के लिए बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड सदस्य के रूप में सहायक केंद्र अधीक्षक-सह-आयुक्त के सचिव बासुदेव प्रसाद, अवर सचिव राकेश चौधरी, रासाबिहारी प्रसाद, उपजनसंपर्क निदेशक आनंद शामिल थे।

**गिरिडीह पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति को हैदराबाद से पकड़ा**

**GIRIDIH :** जिले की हीरोडीह थाना पुलिस शुक्रवार को पत्नी की हत्या के आरोपित पति अनिल यादव को हैदराबाद से गिरफ्तार कर शुक्रवार को गिरिडीह ले लाई। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि अनिल यादव पत्नी को हैदराबाद ले जाने के बहाने पिछले 28 अगस्त को घर हीरोडीह थाना इलाके के टंगपंजला से ससुराल बेरिया दीवान टोला के लिए निकला। इस दौरान पत्नी रिकू देवी को ससुराल बेरिया दीवान टोला से कुछ दूर मुरली पहाड़ी के पास बरहमी से हत्या कर शव को आपत्तिजनक हालत में वहीं फेंक कर हैदराबाद फरार हो गया। मामले की हीरोडीह थाना पुलिस ने सक्रियता से जांच शुरू की तो रिकू देवी की हत्या में पति अनिल यादव का हाथ सामने आया। इसके बाद हीरोडीह पुलिस उसे हैदराबाद से गिरफ्तार कर गिरिडीह लाई।

## घर के बाहर सोए बुजुर्ग की लाठी से पीट-पीट कर हत्या



घर के बाहर जुटी गौड़

● फोटोन न्यूज

**PALAMU :** जिले के मनातू थाना क्षेत्र के जसपुर गांव में गुरुवार रात अज्ञात अपराधियों ने लाठी- डंडे से पीट पीट कर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी। घटना के वक्त बुजुर्ग अपने घर के बाहर सोए हुए थे। घटनास्थल से दो लाठी बरामद हुई है। सूचना मिलने के बाद शुक्रवार सुबह मनातू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए एमआरएसपीसी मेदिनीनीगर भेज दिया है। हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। मृतक को पहचान

राजा यादव (63) के रूप में हुई है। बताया जाता है कि राजा यादव अपने घर के बाहर सोए हुए थे। इसी क्रम में गुरुवार रात करीब 10 बजे लाठी-डंडे से पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी रात 1 हुई। सूचना मिलने पर प्रारंभिक जांच के लिए मनातू थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी। कुछ जानकारी लेकर रात में लौट गई और पुनः सुबह आई। घटनास्थल मनातू थाना से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है और जसपुर घना आबादी वाला गांव है।

**टाटा से पटना के लिए सुबह 6 बजे और बरहमपुर के लिए 5.20 बजे खुलेगी ट्रेन**

## झारखंड को मिलेगा चार वंदे भारत का तोहफा

## ‘मेक रूम फॉर अर्ली लर्निंग’ से बड़ेगी बच्चों की क्षमता



सेमिनार को संबोधित करती उपायुक्त नैन्सी सहाय

● फोटोन न्यूज

**HAZARIBAG :** जिला समाहरणालय सभागार में शुक्रवार को ‘रीडिंग कैम्पेन : मेक रूम फॉर अर्ली लर्निंग’ के अंतर्गत आयोजित जिला स्तरीय सेमिनार में प्रारंभिक शिक्षा और पठन कौशल के महत्व पर विशेष जोर दिया गया। शिक्षा परियोजना परिषद, झारखंड द्वारा रूम टू रीड, आईपीईएल और यूनिसेफ के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में उपायुक्त ने पठन कौशल के विकास और बच्चों में पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के प्रयासों की सराहना की। जिला स्तरीय सेमिनार में उपायुक्त नैन्सी सहाय ने सेमिनार के दौरान बच्चों में पठन कौशल और पढ़ने की

आदत को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की और प्रारंभिक शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पठन कौशल बच्चों के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही, उन्होंने क्षेत्र स्तर पर मौजूद अंतरालों की पहचान करने और सभी हितधारकों के सहयोग से उन समस्याओं को संबोधित करने के लिए प्रभावी रणनीतियाँ विकसित करने पर बल दिया। इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षा अधीक्षक और योजना पदाधिकारी ने भी प्रारंभिक शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला और पठन कौशल को सुदृढ़ करने के लिए सरकारी प्रयासों की प्रशंसा की।

**डीसी के जनता दरबार में फरियादियों ने लगाई गुहार**



**HAZARIBAG :** उपायुक्त नैन्सी सहाय ने शुक्रवार को जनता दरबार लगाया, जिसमें फरियादियों ने अपनी-अपनी समस्याओं का समाधान करने की गुहार लगाई। इसमें शहरी सहित विभिन्न प्रखंडों से 25 आवेदकों ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए, जिनमें मकान मुआवजा, रोजगार, गंभीर बीमारी में मदद, ऑनलाइन रसीद, लॉबित म्यूटेशन, प्रमाण पत्र, आवास, सेवानिवृत्ति पावना, राशनकार्ड, बकाया मानदेय, अवैध कब्जा, अवैध कब्जा, धोखाधड़ी इत्यादि मामले शामिल रहे। उपयुक्त ने दूरदराज से आए ग्रामीणों से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिबिर के माध्यम से सरकार की योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। उन्होंने कहा कई ऐसे मामले हैं, जिनका निपटारा स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है।

## लातेहार : गड्डे में डूबने से तीन बच्चों की मौत



घटनास्थल पर जुटी शालीणों की भीड़

● फोटोन न्यूज

**LATEHAR :** लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत नगड़ा गांव के पास गहरे गड्ढे में डूबने से तीन बच्चों की मौत हो गई। हालांकि सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। जानकारी के अनुसार नगड़ा गांव निवासी रिशु कुमार (6), सुरज कुमार(6) और गोलू कुमार (7) आदि बच्चे गांव के पास ही रेलवे लाइन के निकट खेल रहे थे। इसी दौरान बच्चे पास में ही स्थित एक गहरे गड्ढे में गिर गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचकर बच्चों को ढूँढने का

प्रयास किया, परंतु गड्ढा में पानी काफी अधिक था जिस कारण बच्चों का कुछ अता-पता नहीं चल पा रहा था। बाद में डीजल पंप के माध्यम से गड्ढे के पानी को बाहर निकाला जाने लगा, इसके बाद तीनों बच्चों को बाहर निकाला जा सका। परंतु तब तक तीनों बच्चों की मौत हो गई थी। इधर घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि रेलवे लाइन निर्माण के दौरान ही यह गड्ढा किया गया था और इसे यूं ही छोड़ दिया गया था। इसी कारण आज इतनी बड़ी घटना हो गई।

## ससुराल आए युवक को हाथियों ने कुचला, मौत

**उत्तर प्रदेश के शामली जिला के इस्सीपुर थाना के बसेड़ा गांव का रहने वाला था मृतक**



हाथियों को देखते शालीण

● फोटोन न्यूज

**अचानक खेत से निकले हाथी, मची अफरातफरी**  
हाथियों के अचानक खेत से निकलकर सामने आ जाने के बाद ग्रामीणों में अफरातफरी मच गई। भागने के क्रम में मृतक हाथियों के झुंड के बीच फंस गया। हाथियों ने शौकीन को पड़कर कुचलकर मार डाला। हाथियों का गुस्सा देखकर किसी ग्रामीण की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह शौकीन को बचाने को लेकर कोई उपाय भी सोच सके। इस घटना के बाद हाथियों का झुंड कुंठे जंगल की ओर चला गया। घटना की सूचना कुड़ थाना पुलिस और वन विभाग की टीम को दी गई। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के उपरांत परिजनों को सौंप दिया है।

झुंड विचरण कर रहा है। हाथियों ने अब तक तीन लोगों की जान ले ली है। हाथियों ने दर्जनों मकानों

को ध्वस्त कर दिया है। कई एकड़ में लगी फसल को भी बर्बाद किया है।

## छतरपुर में स्वर्ण व्यवसायी से 15 लाख की लूट, तीन माह में तीन घटनाएं

**एक भी मामले का नहीं हुआ उद्भेदन, व्यापारी चिंतित**

**PHOTON NEWS PALAMU :** जिले के छतरपुर में एक बार फिर स्वर्ण व्यवसायी से 15 लाख की लूट हो गई है। चौरा गांव के समीप स्वर्ण व्यवसायी से हाथियार के बल पर 15 लाख के आभूषणों की लूट हो गई है। तीन माह में तीसरी घटना होने से स्वर्ण कारोबारी में आक्रोश के साथ-साथ हड़कंप मच गया है इस संबंध में शुक्रवार को छतरपुर थाना में मामला दर्ज कराया गया पुलिस एक बार फिर अनुसंधान में जुड़ गई है। यहां यह भी बता दें कि अब तक हुई तीनों घटनाओं में से किसी का उद्भेदन नहीं हो पाया है। जिससे प्रतीत होता है कि पुलिस का सुरक्षा और खुफिया तंत्र इस मामले में फेल है। स्वर्ण व्यवसायी अशोक ज्वेलर्स



घटना की जानकारी देता व्यवसायी

एंड बर्तन दुकान के संचालक अशोक सोनी ने अज्ञात हाथियारबंद अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। अशोक सोनी ने बताया कि उनका सरइंडीह में भी सोने चांदी की दुकान है और वे प्रतिदिन की भाँति बाइक से

आभूषण लेकर छतरपुर से सरइंडीह स्थित अपनी दूसरी दुकान जा रहे थे कि चौरा और चहलथान के बीच सुनसान जगह पर एक काली रंग की राइडर बाइक से दो अपराधी पीछा करते हुए आये और उनकी बाइक को रुकवा कर पिस्टल के बल पर डिकी में रखा डोला, जिसमें सी ग्राम सोना का आभूषण के साथ उधार बाकी की तीन बही थी। उसके अलावे एक और थैला था, जिसमें आठ किलो चांदी के आभूषण थे उसे भी लूटने के बाद लुटेरों ने उनके जेब से मोबाइल लूट कर भाग निकले। उन्होंने बताया कि काफी शोर मचाया जिसके बाद कुछ गांव के लोगों ने लुटेरों का पीछा किया पर लुटेरे तब तक भाग निकले।

## मंत्री ने चतरा में किया सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का उद्घाटन



शिबिर का उद्घाटन करते मंत्री सत्यानंद गोका

● फोटोन न्यूज

**CHATRA :** राज्य के उद्योग व श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने शुक्रवार को सदर प्रखंड के देवरिया पंचायत के ग्राम देवरिया में आयोजित ‘आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके उपरांत लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का विवरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुविधाओं को

पहुँचाने के लिए राज्य सरकार ने सभी पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। यहां आए मामलों का त्वरित रूप से निष्पादन हो रहा है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष नवलकिशोर यादव, जिला परिषद सदस्य चन्द्रदेव गोप, प्रमुख धनवा देवी, उप प्रमुख नीलम देवी, मुखिया गुरुद्वे समेत अन्य कई गणमान्य मौजूद रहे।



## भाजपा का सदस्यता अभियान लोकतांत्रिक जुड़ाव और पार्टी विस्तार का उपक्रम

देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था विस्तार और प्रसार की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लालकिला की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, एक लाख युवाओं को राजनीतिक व्यवस्था में शामिल किया जाना चाहिए, खासतौर पर उन युवाओं को, जिनके परिवार में राजनीति का कोई इतिहास नहीं है। भारत में कई राजनीतिक दलों पर लंबे समय से पारिवारिक सदस्यों का ही वर्चस्व रहा है, जहां सत्ता अक्सर अर्जित करने के बजाय विरासत में मिलती है। यह व्यवस्था क्रम आम नागरिकों के लिए बदलाव लाने के अवसरों को सीमित कर सकता है। बिना किसी राजनीतिक-पारिवारिक संबंध वाले युवाओं को राजनीति में सम्मिलित करने पर ध्यान केंद्रित करके प्रधानमंत्री मोदी परिवारवाद (पारिवारिक शासन) के पुराने मॉडल से अलग होने और राजनीति में नई आवाज और दृष्टिकोणों के लिए द्वार खोलने के विषय में स्पष्ट बयान दे रहे हैं। एक लाख युवा, जिनका राजनीतिक संबंध नहीं है, उनको लाने से राजनीतिक व्यवस्था में नए विचारों और नवीन ऊर्जा का संचार होगा। यह विचार पुराने परिवार केंद्रित मॉडल को भी चुनौती देता है और अधिक समावेशी और योग्यता आधारित राजनीतिक माहौल के लिए व्यापक मंच तैयार करता है। विभिन्न पृष्ठभूमि से आनेवाले युवा नेता वर्तमान समस्याओं के लिए नए समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं और अपनी पीढ़ी की चिंताओं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। हालाँकि, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 2 सितंबर 2024 को एक प्रमुख सदस्यता अभियान का शुरुआत की है। यह प्रमुख पहल लोकतांत्रिक जुड़ाव के लिए पार्टी के समर्पण और अपने आधार का विस्तार करने में उसकी रणनीतिक दूरदर्शिता को दर्शाती है। सदस्यता अभियान उन राजनीतिक दलों के विपरीत है, जो पारिवारिक राजवंशों तक सीमित हैं और परिवारवाद (पारिवारिक शासन) की अवधारणा में उलट्टे हुए हैं, जहां कुछ पार्टियाँ पारिवारिक संबंधों के माध्यम से नेतृत्व को कायम रख रही हैं, वहीं भाजपा एक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपना रही है, जो समावेशिता और व्यापक भागीदारी पर जोर देती है। लाखों नए व्यक्तियों के लिए अपनी पार्टी की सदस्यता खोल कर पार्टी एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करती है, जहां नेतृत्व और प्रभाव विरासत के बजाय योग्यता और जुड़ाव से निर्धारित होते हैं। यह अभियान राजनीतिक भागीदारी के मानदंडों को फिर से परिभाषित करने का एक अच्छा प्रयास है। कुछ परिवारों के इर्द-गिर्द घूमने वाली पार्टियों के विपरीत भाजपा का दृष्टिकोण सभी क्षेत्रों के लोगों को पार्टी में सम्मिलित करता है और लोकतंत्र की सच्ची भावना को दर्शाता है। विविध पृष्ठभूमि से नए सदस्यों को नामांकित करके, भाजपा पारंपरिक वंशवादी मॉडल को चुनौती दे रही है, यह दिखाते हुए कि राजनीतिक प्रभाव केवल जनसमिद्ध अधिकार से नहीं, बल्कि भागीदारी और योगदान के माध्यम से अर्जित किया जा सकता है। लाखों नए सदस्यों को शामिल करने के लिए अपने आधार का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करके भाजपा एक सहभागी राजनीतिक प्रणाली के प्रति अपने समर्पण को उजागर करती है। यह अन्य पार्टियों के विपरीत है, जहां सत्ता अक्सर कुछ परिवारों के भीतर केंद्रित होती है, जिससे उससे बाहर के व्यक्ति के लिए व्यापक जुड़ाव के अवसर सीमित हो जाते हैं। भाजपा की पहल एक अधिक गतिशील और प्रतिनिधि राजनीतिक वातावरण को प्रोत्साहित करती है, जहां नेतृत्व की स्थिति उन सभी के लिए सुलभ है, जो राजनीति में योगदान करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के इच्छुक हैं। तीन व्यापक चरणों में नियोजित यह अभियान एक प्रशासनिक अभ्यास और एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है, जो समावेशिता और जमीनी स्तर पर भागीदारी के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी की सदस्यता को नवीनीकृत करके इस अभियान की शुरुआत की। ऐतिहासिक रूप से भाजपा हर छह साल में यह सदस्यता अभियान चलाती है। हालांकि, महामारी के कारण पिछला चक्र धीमा रहा था। अब सामान्य स्थिति की वापसी के साथ पार्टी नए उत्साह और रणनीतिक योजना के साथ इस महत्वपूर्ण अभियान को फिर से शुरू कर दिया है। सदस्यता अभियान तीन अलग-अलग चरणों में चलेगा। पहला चरण, 2 सितंबर से 15 सितंबर तक, देश भर में नए सदस्यों को नामांकित करने पर केंद्रित होगा। यह चरण अभियान की नींव रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को पार्टी के पाले में लाया जाए। इसके बाद भाजपा दूसरे चरण में प्रवेश करेगी, जो 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा। इस चरण में कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों और सामाजिक समूहों की पहचान करने के लिए प्रारंभिक नामांकन पैटर्न का विस्तृत विश्लेषण शामिल होगा। भाजपा का लक्ष्य एक संतुलित और समावेशी सदस्यता आधार हासिल करना है। अक्टूबर के मध्य से यह अभियान तीसरे चरण में प्रवेश करेगा, जिसमें सक्रिय सदस्यों का नामांकन शामिल है। यह पार्टी के जमीनी नेटवर्क को बढ़ाने और इसके संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। इसके बाद मंडल, जिला और राज्य अध्यक्षों सहित विभिन्न पार्टी पदों के लिए चुनाव होंगे। ये चुनाव पार्टी की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू हैं और इसके भविष्य के नेतृत्व को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस क्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें 15,000 मंडलों में से 9,000 सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है।

### ANALYSIS



डॉ. मयंक चतुर्वेदी

राज्यों के स्तर पर भी अब तक जितनी सरकारें हुईं, जिसमें असम भी शामिल है और आज के वहां जो मुख्यमंत्री हैं, वे हिमंता बिस्वा सरमा भी। उन सभी प्रदेशों और इनके मुख्यमंत्रियों ने शासन स्तर पर योजनाओं के लाभ और सांविधानिक नियमों के अनुसार अल्पसंख्यकों को मिलने वाले हितों में कोई कमी मुसलमानों के लिए कभी नहीं रखी है, जिसमें आज भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के पास मुसलमानों को मिले लाभ के आंकड़े भी मौजूद हैं। इसके बाद भी भारत की ये इस्लामिक संस्था जमीयत उलेमा-ए-हिंद और इन जैसी अन्य इस्लामी संस्थाएं हैं कि इन्हें हर उस सरकार से शिकायत है, विशेषकर उससे जो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करती हैं। कहना न होगा कि हिमंता बिस्वा सरमा के इस 'मियां मुस्लिम' बयान को लेकर व्यर्थ ही जमीयत उलेमा-ए-हिंद टारगेट कर रही है, जबकि वह जानती है कि मुख्यमंत्री बिस्वा सरमा का ये वक्तव्य भारत के मुस्लिम नागरिकों के लिए नहीं है, जो कहा जा रहा है, वह बांग्लादेश के घुसपैठियों के लिए है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के 'मियां मुस्लिम' संबंधी बयान पर इन दिनों एक विशेष वर्ग की ओर से जमकर राजनीति हो रही है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद एवं वे तमाम संगठन इस वर्ग विशेष के अगुआ हैं, जो मुस्लिम हितों की गारंटी ही नहीं लेते, बल्कि सरकार एवं अन्य समाजों के बीच अपनी आवाज यह कहकर बुलंद करते हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ नाइसफरी हो रही है। उनका यह आरोप आम है कि हुकूमत उन पर बहुत जुल्म कर रही है। अब यह अलग बात है कि केंद्र की मोदी सरकार या इससे पहले की कांग्रेस या अन्य सरकारें, जिनके कार्यकाल में लगातार अल्पसंख्यकों में सबसे अधिक लाभ मुसलमानों को दिया गया और उन्होंने बहुत सफलता से उसे उठाया भी है। फिर भी इस वर्ग के अधिकतर आम लोगों को हुकूमत से शिकायत है। दूसरी ओर राज्यों के स्तर पर भी अब तक जितनी सरकारें हुईं, जिसमें असम भी शामिल है और आज के वहां जो मुख्यमंत्री हैं, वे हिमंता बिस्वा सरमा भी। उन सभी प्रदेशों और इनके मुख्यमंत्रियों ने शासन स्तर पर योजनाओं के लाभ और सांविधानिक नियमों के अनुसार अल्पसंख्यकों को मिलने वाले हितों में कोई कमी मुसलमानों के लिए कभी नहीं रखी है, जिसमें आज भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के पास मुसलमानों को मिले लाभ के आंकड़े भी मौजूद हैं। इसके बाद भी भारत की ये इस्लामिक संस्था जमीयत उलेमा-ए-हिंद और इन जैसी अन्य इस्लामी संस्थाएं हैं कि इन्हें हर उस सरकार से शिकायत है, विशेषकर उससे जो भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करती हैं। कहना न होगा कि हिमंता बिस्वा सरमा के

इस 'मियां मुस्लिम' बयान को लेकर व्यर्थ ही जमीयत उलेमा-ए-हिंद टारगेट कर रही है, जबकि वह जानती है कि मुख्यमंत्री बिस्वा सरमा का ये वक्तव्य भारत के मुस्लिम नागरिकों के लिए नहीं है, जो कहा जा रहा है, वह बांग्लादेश के घुसपैठियों के लिए है। फिर भी उसे इस शब्द के बोलने पर आपत्ति है। सोचने वाली बात है कि जमीयत को ये इस हद तक बुरा लग गया कि उसने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ से मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई करने तक का आग्रह कर डाला। आश्चर्य यह भी है कि जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी सीजेआई तक ही नहीं रुकते। वह गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर असम के मुख्यमंत्री पर तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जमीयत चीफ ने मुख्यमंत्री हिमंता के बयान को संपूर्ण भारत के मुसलमानों से भी जोड़ दिया है। कह रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री का दिया यह बयान संपूर्ण भारत के मुसलमानों को एक विशेष नजरिए से देखता है। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मियां बुला कर सीएम ने उन्हें दूसरे दर्जे के नागरिक का दर्जा देने की कोशिश की है। अब जरा मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का पक्ष भी जान लेना चाहिए। असम कैबिनेट ने कुछ समय पहले ही राज्य की स्वदेशी मुस्लिम आबादी के सामाजिक- आर्थिक सर्वेक्षण को संजूरी दी थी। साल 2022 में पांच मुस्लिम वर्गों की पहचान करके उन्हें स्वदेशी असमिया मुसलमानों के रूप में मान्यता दी गई। ये सभी असमिया भाषा बोलने वाले लोग हैं, किंतु दूसरा एक और समुदाय है, जिसे असम में मियां मुसलमान कहा गया है और ये लोग बांग्लाभाषी हैं और उनमें जो संख्या बांग्लादेश से आकर यहां बस गई

है, उस जनसंख्या का अनुपात 90 प्रतिशत से अधिक बताया जाता है। इसलिए इस मुस्लिम आबादी को लेकर अक्सर यहां विवाद होता है। यहां हिमंता बिस्वा सरकार एक फिल्टर लगाने की बात करती है, ताकि बाहरी मुस्लिमों की पहचान आसान हो और उन्हें बाहर किया जा सके। हिमंता बिस्वा कहते हैं, मैं असम को मियां भूमि नहीं बनने दूंगा। असम के जनसांख्यिकी को परिवर्तित करने और स्थानीय लोगों को अल्पसंख्यक में लाने के लिए एक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अतिक्रमण चल रहा है। यह केवल मैं नहीं कह रहा, बल्कि स्वर्गीय गोपीनाथ बोरदोलोई, विष्णुग्राम मेधी और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है। यहां समझनेवाली बात यह भी है कि असम को छोड़ कर सभी उत्तर-पूर्वी राज्यों में यह कानून है कि गैर-स्थानीय लोग भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकते। चूंकि असम में ऐसा कानून नहीं है, इसलिए बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बसने के लिए विकल्प के तौर पर इस राज्य को चुना है, जिससे उन्हें भूमि व अन्य संबंधित अधिकार जैसे-सरकारी सहायता, रोजगार, चिकित्सा-लाभ आदि प्राप्त करने में आसान मदद मिलती है। वस्तुतः यही कारण है कि आज यहां बांग्लादेशी घुसपैठियों ने राज्य की जनसांख्यिकीय संरचना को पूरी तरह भारी बदलाव देखने में आया और राज्य के नौ में से छह जिले मुस्लिम बहुल हो गए। इन आंकड़ों पर भी गौर करें कि वर्ष 1971 में जो असम राज्य में हिंदुओं की आबादी 72.5 प्रतिशत थी, वह समय के साथ बढ़ने के स्थान पर घटती चली गई। 2001 में घटकर

64.9 और 2011 में 61.46 प्रतिशत रह गई। इसके उलट मुसलमान हैं कि उनकी जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि होती जा रही है। 1971 में मुस्लिम आबादी 24.6 प्रतिशत थी, जो 2001 में बढ़कर 30.9 और 2011 में 34.2 प्रतिशत हो गई। यानी 10 वर्ष में मुस्लिम आबादी 40 प्रतिशत बढ़ गई। आज मुस्लिमों की असम में बढ़ती जनसंख्या के लिए तीन अनुमान हमारे सामने हैं। एक हितेश्वर सैकिया को वर्ष 1992 में तत्कालीन मुख्यमंत्री असम थे, उनके अनुसार बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या 32 लाख थी। दो- 2004 में कांग्रेस की मनमोहन-संग्राम सरकार ने इस बात को संसद में स्वीकारा था कि घुसपैठियों की संख्या 50 लाख तक हो गई है। तीन- उसके बाद आई मोदी सरकार ने वर्ष 2016 में इन घुसपैठियों की जनसंख्या 80 लाख से ऊपर होना बताया था। जो 2011 में राज्य की कुल आबादी 3.3 करोड़ का 25 प्रतिशत हैं। अभी हाल ही में किए गए तीन अलग शोधों में यह सामने आ चुका है कि हिंदू असम में वर्ष 2040 से 2051 के बीच मुसलमानों की तुलना में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। यहां दिक्कत यह है कि इस मुस्लिम बहुल असम में बांग्लादेशी मूल के लोग सबसे अधिक होंगे। कहना होगा कि यह मुस्लिम जनसंख्या का आंकड़ा अचानक नहीं है। यह उनकी जन्म दर के संख्यात्मक विस्फोट का परिणाम है। बांग्लादेश से घुसपैठ नहीं रुक पाने के कारण से ही यह बार-बार कहा जा रहा है कि असम का 20 वर्ष में मुस्लिमीकरण हो जाएगा। अभी नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर भी सभी ने देखा कि कैसे इसे विवाद का विषय है इस्लामवादियों ने पूरे देश में बना दिया था। इसके माध्यम से पूरे

विश्व को ये संदेश देने की कोशिश की गई कि मोदी सरकार असम में मुसलमानों को प्रताड़ित कर रही है। यहां पूरे असम को आग के हवाले करने में कोई हिचक इन इस्लामवादियों में नहीं थी, जबकि इससे जुड़ी हकीकत यह है कि इसे 1951 में असम के सभी निवासियों के लिए 2014 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर लागू किया गया था। उद्देश्य भी साफ था कि 25 मार्च 1971 के पहले से जो राज्य में रह रहे हैं, उन लोगों या उनके पूर्वजों की पहचान की जाएगी और उस आधार पर जिनहें 1951 का नागरिक पाया जाएगा, वे अद्यतन एनआरसी में शामिल हो जाएंगे। पूरा एनआरसी सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में किया गया था, किंतु इसके बाद भी व्यापक तौर पर एक बड़ी संख्या जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की है, अपना नाम इसमें डलवाने में कामयाब हो गए। यहां फर्जी पहचान के आधार पर कई बांग्लादेशियों ने भूमि-भवन, सरकारी लाभ भी प्राप्त कर लिए हैं। यही कारण है कि भाषाई तौर पर इनकी असली पहचान कर इन्हें राज्य से बाहर करना आज बहुत कठिन हो गया है। इस सब के बीच हमें यह जरूर याद रखना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2015 में उपमन्यु हजारीका आयोग गठित किया गया था। इस आयोग ने बांग्लादेश के साथ सटी सभी की स्थिति पर अदालत को अपनी अहम चार रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें घुसपैठ रोकने का एकमात्र उपाय ही बताया गया था कि संसम में कानून बनाकर भूमि, रोजगार, व्यापार आदि सिर्फ उनके लिए आश्रित किया जाए, जिनके नाम या जिनके पूर्वजों के नाम 1951 के एनआरसी में मौजूद हैं, वे असम के निवासी माने जाएं और अन्य को इससे बाहर कर दिया जाए।

# चीन से व्यापार : आयात और निर्यात का उलझा समीकरण

थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष 2024 के पहले छह महीनों (जनवरी से जून 2024) के दौरान भारत का चीन के साथ अब तक का सर्वाधिक व्यापार घाटा दर्ज किया गया है, जो 41.6 अरब डॉलर है। इस अवधि में चीन से आयात बढ़ कर 50.1 अरब डॉलर हो गया, जबकि चीन को सिर्फ 8.5 अरब डॉलर का निर्यात किया गया। पिछले संपूर्ण वित्त वर्ष 2023-24 में चीन के साथ भारत के व्यापार को देखें तो पाते हैं कि चीन से आयात 101.75 अरब डॉलर हुआ था। चीन को निर्यात 16.66 अरब डॉलर रहा तथा चीन के साथ व्यापार घाटा 85.09 अरब डॉलर रहा है। निश्चित रूप से चीन के साथ बढ़ता हुआ व्यापार घाटा देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक प्रोत्साहन

आधारित उत्पादन (पीएलआई) के तहत एपीआई का उत्पादन बढ़ा कर इसके चीन से बड़े पैमाने पर होने वाले आयात में कमी की जा रही है। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक चीन को खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के रणनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि इन दिनों भारत-चीन के व्यापार से संबंधित प्रकाशित हो रही विभिन्न वैश्विक आर्थिक वित्तीय संगठनों की रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि इस समय भारत के पास चीन से आयात घटाने और वैश्विक निर्यात में भारत का हिस्सा बढ़ाए जाने की संभावनाएं हैं। वैश्विक वित्तीय कंपनी नोमूरा ने भी हाल ही में अपनी रिपोर्ट में कहा कि चीन से ग्लोबल कंपनियों बाहर निकल रही हैं जिसका बड़ा फायदा भारत को मिलता दिख रहा है। नोमूरा द्वारा चाईना प्लस वन स्ट्रेटजी पॉलिसी को लेकर

130 फर्मों के साथ सर्वे किया गया है। कहा गया है कि खासतौर से भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, सेमीकंडक्टर (एसेंबलिंग, टेस्टिंग), एनर्जी (सोलर) के अलावा फार्मास्युटिकल्स सेक्टर की कंपनियों का भारत में हरसंभव सुविधा देकर स्वागत किया जाना होगा। यह भी महत्वपूर्ण है कि जी-20 की नई शक्ति से सुसज्जित भारत नए वैश्विक आपूर्तिकर्ता देश की भूमिका में उभर कर सामने आया है और चीन को आर्थिक टक्कर देने की स्थिति में है। निश्चित रूप से दुनिया के बाजार में चीन का दबदबा तोड़ने के परिप्रेक्ष्य में यूरोपीय, अमरीका और अन्य कई देश चीन से आयात के बढ़ते खतरों के मद्देनजर चीनी आयातों पर असाधारण आयात प्रतिबंध लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। विगत 12 जून को यूरोपीय आयोग ने चीन में बने इलेक्ट्रिक

वाहनों पर 48 प्रतिशत तक आयात शुल्क लगाना सुनिश्चित किया है। पिछले कई वर्षों से यूरोपीय देशों की चीन से आयात पर शुल्क की दरें 10 प्रतिशत तक ही सीमित रही हैं। ऐसे में विभिन्न देशों द्वारा चीन से आयात होने वाले अनेक उत्पादों पर लगातार बढ़ता शुल्क चीन के आयात को हतोत्साहित करने की एक अहम पहल है, ऐसे में इन देशों में भारत से निर्यात की संभावनाएं बढ़ी हैं। वैसे चीन का भारतीय बाजारों पर जो दबदबा बना हुआ है, उसमें कमी आती दिखाई दे सकती है। यह बात महत्वपूर्ण है कि मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर देश से निर्यात और रोजगार सृजन दोनों में अहम योगदान देता है और इसके प्रोत्साहन के लिए इस बजट में खास ख्याल रखा गया है। वित्तमंत्री ने बजट में देश के 100 शहरों में प्लग एंड प्ले वाले औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की है। केंद्र, राज्य और निजी सेक्टर की आपसी

सहभागिता से प्लग एंड प्ले सुविधा वाले औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। उद्यमी को ऐसे औद्योगिक पार्क में जाकर सिर्फ उत्पादन शुरू करना होता है। नए बजट प्रावधानों के तहत 100 शहरों में प्लग एंड प्ले वाले सुविधा वाले औद्योगिक क्लस्टर या पार्क के विकसित होने से कम से कम 100 प्रकार के आइटम का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकता है। वर्ष 2024-25 के बजट में वित्तमंत्री ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को निर्यात बढ़ाने के मद्देनजर सशक्त बनाया है। साथ ही इस सेक्टर के आयात में कमी के मद्देनजर प्रावधान किए गए हैं। निःस्संदेह एक बार फिर देश के करोड़ों लोगों को चीनी उत्पादों की जगह स्वदेशी उत्पादों के उपयोग के नए संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। इस बात को भी समझना होगा कि चीन से व्यापारिक असंतुलन की गंभीर चुनौती के लिए सिर्फ सरकार ही

जिम्मेदार नहीं है। चीन के साथ व्यापार असंतुलन के लिए सीधे तौर पर देश का उद्योग-कारोबार और देश की कंपनियां भी जिम्मेदार हैं, जिनके साथ कल-पुर्जे सहित संसाधनों के विभिन्न स्रोत और मध्यस्थ विकसित करने में अपनी प्रभावी भूमिका नहीं निभाई गई है। साथ ही देश की बड़ी कंपनियों को शोध एवं नवाचार के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ना होगा। इस बात पर भी गंभीरतापूर्वक ध्यान देना होगा कि जिस तरह हाल ही में यूरोपीय यूनियन और अन्य विकसित देशों द्वारा चीन से आयात नियंत्रित करने के लिए गैर टैरिफ अवरोधों के साथ अन्य आयात प्रतिबंधों को असाधारण रूप से बढ़ाया गया है, उसी तरह भारत को संरक्षणवाद के तरीके अपनाते हुए चीन से तेजी से बढ़ रहे आयात और चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को नियंत्रित करने के लिए रणनीतिक रूप से आगे बढ़ना होगा।

## Social Media Corner

### सब के हक में...

भारत में जनभागीदारी और जनअवलोकन से जल संरक्षण और पृकृति संरक्षण का अतूटा अभियान चल रहा है। गुजरात के सूरत में 'जल संवय जनभागीदारी पहल' का शुभारंभ कर अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'एक्स' पर पोस्ट)



चक दे इंडिया, चक दे हरियाणा! दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले हमारे प्रतिभाशाली वैपियन विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया से 10 राजाजी मार्ग पर मुलाकात। हमें आप दोनों पर गर्व है। (मल्लिकार्जुन खड़गे का 'एक्स' पर पोस्ट)



लोकतंत्र की प्रथम इकाई पंचायत के जनप्रतिनिधि अपनी जायज मांगों को लेकर धरन पर बैठे हुए हैं। नौकरी के लिए युवा अपनी जान गंवा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों की व्यवस्था चलाने वाले मुखिया संघ, जल सहिया, कंप्यूटर ऑपरेटर, पंचायत सचिव जैसे संगठन धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इनकी समस्याओं का समाधान करने की बजाय दिल्ली में नाच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने ही सभी संगठनों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा और हेमंत सोरेन जैसे संवेदनहीन मुख्यमंत्री के कुशासन से झारखंड की जनता को मुक्ति दिलाई जाएगी। (पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी का 'एक्स' पर पोस्ट)



अमेरिका में बसे लाखों भारतीय डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं या कमला हैरिस के पक्ष में। अगर मीडिया पर आ रही खबरों पर यकीन करें तो कमला हैरिस को आज के दिन अधिक लोकप्रिय बताया जा रहा है। कमला की लोकप्रियता प्रतिदिन बढ़ने की बात कही जा रही है। भारत सरकार किसे विजयी देखना चाहती है। यह तय है कि जो भी जीतगा भारत सरकार उसके साथ तालमेल बिठा कर काम करेगी ही। यह बात भारत-अमेरिका के गहरे द्विपक्षीय संबंधों की रोशनी में कही जा सकती है, जो लगातार मजबूत हो रहे हैं। एक बात जान लें कि अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के एकमुश्त वोट कमला हैरिस को नहीं मिलेंगे, कुछ वोट तो बंटेंगे ही। कुछ वोट ट्रंप के खाते में भी जाएंगे, पर कमला हैरिस को भारतीय अपना तो मानते हैं। कमला हैरिस की मां श्यामला गोपालन तमिलनाडु के एक कुलीन ब्राह्मण परिवार से थीं। यह

## अमेरिका का अगला राष्ट्रपति

समाज अपनी बेटियों की शिक्षा पर बहुत ध्यान देता है। इसलिए इस परिवार ने श्यामला गोपालन को अपने सपनों को पूरा करने के लिए नई दिल्ली जाने की अनुमति दी, जहां उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। श्यामला के पिता पीवी गोपालन सरकारी सेवा में ही थे और मां सफल गृहिणी थीं। गोपालन जी सरकारी दफ्तर में टाइपिस्ट थे और अपनी लगन और ईमानदारी के सहारे पदोन्नति पाते रहे। वह अपनी नौकरी के सिलसिले में मद्रास, नई दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में रहे। डीयू से 19 साल की उम्र में डिग्री लेने के बाद कमला हैरिस का मां श्यामला ने उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए अमेरिका का रुख किया। उन्होंने अमेरिका में एक अफ्रीकी मूल के शख्स से शादी की, जिसका परिवार कैलिफोर्निया देश जर्मका में बस गया था। इस लिहाज से देखा जाए तो कमला हैरिस को भारतीय और अफ्रीकी कहीं न कहीं अपने से जुड़ा मानते हैं। उधर, ट्रंप का भी

अपना खास जनाधार है। वह 2016-2020 के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं। ट्रंप वह व्यक्ति भी हैं, जिन्होंने यूक्रेन और गाजा में संघर्षों को समाप्त करने का वादा किया है, जो लेबनान तक फैल गया है। वह इसे लेकर कितने गंभीर हैं या वे इसमें कितना सफल होंगे, यह अनुमान का विषय है। लेकिन, कम से कम उन्होंने वादा तो किया ही है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकन भी गाजा में चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए अपने ढंग से कुछ काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि इससे डेमोक्रेटिक पार्टी को मदद मिलेगी। लेकिन, न तो बाइडेन और न ही कमला हैरिस ने अब तक गाजा में शांति लाने का कोई ठोस इरादा दिखाया है। ऐसे में क्या ट्रंप की जीत को विश्व शांति के लिए भी मतदाता अच्छा मानेंगे। अब जरा बात भारत-अमेरिका संबंधों की। ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इससे भारत-अमेरिका संबंधों पर कोई खास फर्क नहीं

पड़ेगा कि व्हाइट हाउस में ट्रंप पहुंचते हैं या कमला हैरिस। भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध बेहतर होते रहेंगे, यही अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विश्लेषक मानते हैं। दोनों देशों के संबंध उस दायरे से कहीं आगे जाते हैं, जब सत्ता परिवर्तन का असर संबंधों पर होता है। इन संबंधों में किसी पर्सनालिटी का असर नहीं हो सकता। हां, दोनों देशों के नेताओं के निजी संबंधों से स्थिति और बेहतर हो सकती है। यह हमने नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा, फिर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप और उसके बाद मोदी और बाइडेन के समय देखा। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से अमेरिका के दो पूर्व राष्ट्रपतियों बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक अलग पर्सनल केमिस्ट्री विकसित की थी, वैसी ही केमिस्ट्री उनकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ भी बनी। कुछ अस्वस्थ होने के बावजूद पिछले साल बाइडेन जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने नई दिल्ली आए।

## पुतिन और मध्यस्थता

जब रूस और यूक्रेन भयानक युद्ध की आग में झुलस रहे हों, तब शांति का एक हल्का सा झोंका भी खुशी व उम्मीद से भर देता है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कहा कि भारत, चीन और ब्राजील संभावित शांति-वार्ता में मध्यस्थ के रूप में काम कर सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति ने इस मूल्य पर यह भी वाद दिलाया कि युद्ध के शुरूआती हफ्तों में इस्तांबुल में हुई वार्ता में रूसी और यूक्रेनी वाताकारों के बीच एक शुरूआती समझौता हुआ था, जिसे कभी लागू नहीं किया गया, वही छूटा हुआ समझौता आगे शांति-वार्ता के लिए जमीन तैयार कर सकता है। पुतिन अगर वाकई युद्ध से अलग कुछ सोच रहे हैं, तो उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। वास्तव में, यह ऐसा युद्ध है, जो मानो दो भाइयों के बीच हो रहा है और इसके नतीजे कभी सुखद नहीं होंगे। अंततः वार्ता की मेज पर अमन-चैन की राह तैयार करनी पड़ेगी, यह समझ जितनी जल्दी जाग जाए, दुनिया के लिए उतना ही अच्छा है। इस युद्ध में हार-जीत बहुत मुश्किल है। रूस हार नहीं सकता और यूक्रेन को अमेरिका हारने नहीं देगा। अब पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या वाकई रूस शांति चाहता है। क्या भारत, चीन या ब्राजील को आगे करते हुए पुतिन शांति-वार्ता के लिए लालायित हैं। क्या शांति-वार्ता या मध्यस्थता की चर्चा छेड़ना रूस की युद्ध रणनीति का नतीजा है। पुतिन ने युद्ध में जैसी निर्ममता का परिचय दिया है, उसे जल्दी भुलाया नहीं जा सकता। एक दशक पहले तक उनकी छवि बहुत अच्छी थी, पर धीरे-धीरे उनकी उम्रता बढ़ती गई और दूसरे देशों के प्रति बैर-भाव भी बढ़ता चला गया। साल 2022 से ही युद्ध जारी है और ढाई वर्ष से ज्यादा समय बीत चुका है, अब भी युद्ध का अंत नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदारी पुतिन के खाते में ही दर्ज है। पुतिन ने ही पहले हमला किया और कायदे से उन्हें ही पहले हथियार पीछे करने चाहिए।





## Chinese handshake costing Pak dear in Balochistan

RECENT attacks on multiple targets in Pakistan’s Balochistan province mark an escalation in hostilities. The attacks were a consequence of festering problems and the damage to Balochistan’s sociocultural and economic fabric. A major reason for the attacks was the CPEC (China-Pakistan Economic Corridor) desire to run an ambitious communications corridor from Xinjiang to Gwadar through Balochistan, a move not supported by residents of the province.

A close ally of China for decades, Pakistan has sought to use the Chinese largesse to address many of its problems. While their India-centred agenda has several convergences, Pakistan hoped that China would align with it against India. A review of the period since 1947 reveals that while China’s diplomatic and military support to Pakistan may have been overtly nuanced on occasions, its covert facilitation and huge military supplies are central to Pakistan’s operational capability and vital for Pakistan’s missile, nuclear and submarine development. Unfortunately, strategic relations between unequals demand concessions from the less strong partner. From the act of ceding the Shaksgam valley of Kashmir to China in 1963, based on a specious boundary settlement, to the hosting of the CPEC and virtually surrendering control of northern Gilgit, the list of Pakistan’s strategic giveaways to China is long. Enabling the Chinese to reach the high waters of the Arabian Sea through the Khunjerab Pass on the Karakoram mountains up to the port of Gwadar has been one of the major giveaways. This mega plan promises to transform Pakistan with a goal of 2.3 million jobs, 2-2.5 per cent additional growth and an enormous upgrade of road, rail, industrial and electrical facilities. For China, its 12,000-km oil transportation journey from the Gulf gets reduced to 2,395 km, with a saving of about \$2 billion a year (according to present estimates). It also negates China’s Malacca dilemma and furthers its ambition to have a base in the Arabian Sea. The heart of the CPEC projects lies in Balochistan, a province that has never been integrated and remains restive. For the Balochis, their identity, autonomy, human rights abuse by the Pakistani state and the extraction of economic gains without returns remain major troubling issues.

Historically, Pakistan has chosen alliances mostly based on security and development-related priorities. The country’s engagement with the US has given it a slew of advantages. Pakistan’s centrality to the conflicts in Afghanistan, coupled with its own convoluted priorities, however, left it more divided, scarred and economically deprived. Its flawed vision of using covert entities to get leverage in Afghanistan and seek strategic depth has unravelled. Consequently, insecurity prevails in the region, including Afghanistan. In its pursuit of powerful allies like the US and China, Pakistan has neglected to integrate the western provinces and their people. A complex and twisted issue that has fomented resentment among Afghans, Pathans and Balochis is the Punjabi centralism and exceptionalism. Further, Pakistan has always preferred to use military force to deal with resistance movements instead of focusing on reconciliation. This has caused the Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) and the Baloch movements to converge in resisting the Pakistani approach.

In February 2022, then Pakistani Interior Minister Sheikh Rasheed Ahmad officially acknowledged this reality. Later, in November 2022, ill-fated talks with the TTP collapsed. Five main Baloch nationalist groups have seldom been approached for reconciliation. The brutal killing of Akbar Bugti, a Baloch leader, in 2006 by the Pakistani army marked a definitive break for the Balochis. For Pakistan, pursuing powerful and demanding foreign powers while letting deep internal fractures widen is hardly strategic wisdom.

At 11,317, the year 2009 saw the highest number of fatalities because of internal conflict in Pakistan. The number slumped to 365 in 2019 due to military measures and its focus on Afghanistan.

## Assembly polls ignite J&K’s hopes for restoration of statehood

After years of Central rule, there is a strong desire among people to elect a government that can represent their voices.

THE three-phase Assembly elections in Jammu and Kashmir (J&K), starting on September 18, are historic, being the first after the state became a Union Territory (UT). The last Assembly elections were held in 2014 under entirely different political circumstances. As a UT, J&K has undergone significant changes since August 5, 2019. The Reorganisation Act, 2019, implemented following these changes, has resulted in new constituencies, based on the recommendations of the Delimitation Commission. The UT is abuzz with political activity. Participants include traditional regional parties, some separatist organisations, and even individuals charged under the Unlawful Activities Prevention Act (UAPA). Jamaat-e-Islami Jammu Kashmir, banned under Section 3(1) of UAPA, has fielded candidates in Kulgam, Pulwama and other areas of South Kashmir. Sugra Barkati, daughter of jailed separatist leader Sarjan Barkati who was the face of the 2016 protests in South Kashmir, had last week filed nomination on his behalf, which was rejected. Barkati may now contest from the Ganderbal Assembly seat in Central Kashmir. The brother of Afzal Guru, a convict in the Parliament attack case, may also contest. Engineer Rashid brought noticeable changes to the politics of the Valley. There was already a strong sentiment in his favour, but it remains uncertain whether a similar sentiment will be seen again. If Rashid is released from jail, he might create an impact that could benefit his Awami Ittehad Party candidates. However, without him, the main contest seems to be between the Congress-National Conference (NC) alliance and the BJP, with the Peoples Democratic Party (PDP) following behind. In this year’s parliamentary election, the Congress-NC alliance secured over 41 per cent of the votes, while the BJP received 24 per cent and the PDP 8 per cent. Whether the same pattern will be observed in the Assembly elections remains uncertain. In the parliamentary elections, people in Jammu had voted for the BJP in support of Prime Minister Narendra Modi. However, dissatisfaction was seen among



exchange. Both the NC and PDP have called for resuming talks with Pakistan. The manifestos of the NC and the PDP are almost similar. However, Mehbooba Mufti has added the “resolution of the Kashmir issue” to the PDP’s manifesto promises. What this means and how she intends to achieve it remains unclear though. Engineer Rashid’s party has promised to prioritise “land security,” and address the “issue of prisoners in various jails across the country.” In the Kashmir valley too, the BJP faces major challenges. While its ally Sajjad Lone of the People’s Conference performed well in the parliamentary elections, others did not achieve success. Traditional regional parties like the NC and

Congress are expected to have an advantage, and the PDP may also see gains. There is, however, some residual dissatisfaction with the PDP due to its earlier campaign against the BJP in 2014, and then its subsequent coalition with the same party. The NC appears to be the party that has made the most gains in the last four to five years.

There had been a consistent demand for the restoration of statehood before the elections. There is a widespread perception that unless the Central Government restores statehood, the next government may find it hard to address the aspirations of the people. Nevertheless, the formation of a local government will be a crucial first step toward raising voices and passing resolutions in the Assembly that could eventually lead to meaningful change. This election is seen as a clash between pre-2019 and post-2019 politics. Despite this, many across J&K, regardless of their identity, want statehood to be restored. Therefore, there is interest in parties, alliances or ideologies that promise a quick restoration of statehood.

The elections are expected to see a considerable increase in the voter turnout. Factors that previously discouraged participation, such as boycotts and threats from terror groups, are now largely absent. People are not likely to vote based on what is offered in party manifestos but rather to restore democracy in the region. After years of direct rule from New Delhi, there is a strong desire among the people to elect a government that can represent their voices.

Some narratives at the national level had suggested that Governor’s rule was beneficial and welcomed by the people. While it is true that there was widespread resentment against earlier state governments, as well as corruption and backdoor appointments in the government machinery, it is not a corollary that the people desire continuous Governor’s rule, regardless of how effective it may have been in the past. Given the current political scenario, there is a high possibility of a coalition government being formed.

## India’s export hurdles

Need to wrest the initiative from rivals

THE World Bank’s (WB) latest India Development Update has some good news to offer: The Indian economy continues to grow at a healthy pace despite challenging global conditions. The WB has upwardly revised the growth forecast for the country’s economy to 7 per cent from the earlier projection of 6.6 per cent in the current financial year. The not-so-good news is that India is losing out to competitors like Vietnam and Bangladesh among low-cost manufacturing export hubs. As per the WB, India needs to diversify its export basket and leverage global value chains to reach its \$1-trillion merchandise exports goal by 2030. The report’s unwritten message for India is that there is no room for complacency on the trade front. It is obvious that the ‘Make in India’ push is not really translating into a ‘Make for the world’ success story. And what won’t be music to the Modi government’s ears is the fact that the nation’s share



in the global exports of apparel, leather, textiles and footwear has declined from 4.5 per cent in 2013 to 3.5 per cent in 2022. The corresponding share of Bangladesh

touched 5.1 per cent in 2022, while that of Vietnam reached 5.9 per cent. No less worrisome is India’s increasing trade deficit (the difference between imports and exports) with China. Amid the military stalemate in eastern Ladakh, Beijing is upstaging Delhi with its no-holds-barred economic muscle-flexing. From umbrellas to musical items and toys, there is no stopping the influx of Chinese goods into India.

Political and economic instability in Bangladesh has given India an opportunity to regain lost ground. The key is to reduce production costs and improve productivity without compromising on quality. Considering India’s reluctance to be part of mega trade blocs, a greater emphasis on bilateral Free Trade Agreements with Western and Gulf nations is the best bet to counter the Vietnamese-Chinese challenge.

## Old wine in a new biotech bottle

Biotechnology for Economy, Environment & Employment Policy silent on timelines, investments

CLIMATE change, energy transition, waste management, sustainability, agricultural productivity, the need for new health tools and much more. India can not only address these pressing challenges through the application of biotechnology but can do so while generating jobs and contributing to the national economy. This is what the Biotechnology for Economy, Environment and Employment (BioE3) Policy released by the government on August 31 would have us believe. The only caveat is that the policy is silent on the timeframe, the quantum of investment and human resources required, the possible number or types of jobs that will be generated and the pathway to achieve the goal. The ‘vision’ of the policy is to “set Bharat at the forefront of the future that is more sustainable and responsive to global challenges by accelerating and harnessing biomanufacturing solutions that encompass diverse bioeconomic activities while safeguarding environmental and climate impacts.” The ‘goal’ of the policy is “to fast-track innovation-to-technology” by weaving together fragmented activities under the umbrella of biomanufacturing and to incentivise “concrete options to build a sustainable future”. The overall ‘objective’ is to present a framework to ensure the adoption of cutting-edge technologies and accelerate the development and production of bio-based high-value products. While presenting the policy, Department of Biotechnology (DBT) Secretary Rajesh Gokhale declared that the goal was the ‘industrialisation of biology’ and making India a global leader in this field. If one cuts the fluff, all that the policy document indicates is the government’s intent to promote biotechnology-based industry and the use of new tools like digitalisation, artificial intelligence and machine learning. If that is so, there

is nothing new here because the last policy document the DBT released in 2021 — National Biotechnology Development Strategy (2021-25) — said precisely the same thing but it was backed with timelines, financial targets and clear pathways. The goal set in 2021 by the DBT was to develop a biotechnology-led ‘knowledge and innovation-driven bioeconomy’ and make India a ‘global biomanufacturing hub’ by 2025. This was to be achieved by building a skilled workforce and enabling infrastructure for industry like bio-foundries, and incentives to the industry for developing and producing affordable products. The thrust areas identified in 2021 were climate change, food security, green energy, waste management, etc. The list has been repeated in the 2024 document, but the DBT has cleverly made no mention of previous policies and strategies to avoid questions being asked about missed goals. The only follow-up action since 2021 is a new scheme to promote bio-foundries announced in the 2024-25 Budget.

In the past four decades, biotechnology has demonstrated its potential in applications ranging from new vaccines and novel crop varieties to environmental cleanup using microbes. Indian policymakers recognised its potential early on, establishing a dedicated government department for its promotion in 1986. The DBT, in its formative years, focused on building research and education capabilities, which has made India a significant player in this field. However, the biotech-based industry was slow to pick up due to reasons such as a lack of venture capital and an enabling environment. Whatever industry developed was not a result of the DBT’s programmes. The poster boy of the Indian biotech industry, Biocon, predates the formation of the DBT, and other pioneers like Shantha Biotech and Bharat Biotech took root with the help of risk

financing by another government body, the Technology Development Board.

In the 2000s, the governments of Karnataka and then undivided Andhra Pradesh rolled out their policies that gave incentives to the biotech industry. The success of the Genome Valley and the IKP Knowledge Park in Hyderabad are shining examples



of a state-sponsored technology cluster developing with the active participation of the private sector. It was only in 2012 that the DBT established a commercial arm for industry promotion — the Biotechnology Industry Research Assistance Council. The government should boost the industrial base in biotechnology by leveraging existing strengths and learning from the experience. However, the new policy does not mention successful models like the Genome Valley or IKP Knowledge Park. Instead, it has rehashed the same

concept and given it a new name (Mulankur Bio-Enabler Hub). These hubs, the policy says, will ‘augment discovery and translational research’ and ‘support facilities for pilot scale and pre-commercial scale research’. This is what the functional technology clusters are doing and have successfully incubated firms that have grown to become billion-dollar companies. While unveiling a grand utopian vision of solving all problems, the policy underplays the key role of regulation (it calls regulation a ‘roadblock’), the need to invest in developing technical manpower and boosting state funding for fundamental research. Regulation is critical as biomanufacturing is all about genetically modified and other organisms. At present, regulation is fragmented and opaque. The Biotechnology Regulatory Authority of India Bill has been in cold storage since 2013. Before embarking upon building a large-scale biotech industry, it would be prudent to develop a robust, autonomous and statutory regulatory system.

The DBT Secretary talks about a ‘new industrial revolution’ fuelled by biotechnology, like the much-celebrated IT Revolution. He should remember that the communication revolution was triggered not by a policy but by the government’s resolve to develop a digital telephone exchange from scratch with a committed investment and a tight deadline. In the same way, it was the state-promoted Software Technology Parks scheme that led to an exponential growth of the software industry and the IT Revolution. Decisive government actions are more important than policy pronouncements.





more nutritious and varied food options."

### The issue of anaemia and iron intake

Despite this improvement in dietary diversity, the report also points out that efforts to boost iron intake have not yielded the desired results. Anaemia remains a widespread issue in the country. The paper suggests that the government's approach to fortifying cereals with iron, while simple to implement, may not be enough to combat anaemia effectively. "Improving iron intake and reducing anaemia might require promoting more diverse diets rather than relying on fortification of cereals alone," the paper mentioned. The report also highlights improvements in dietary diversity across states and Union Territories. Northeastern states like Sikkim, Arunachal Pradesh, and Tripura have seen some of the most notable gains. In other regions, states like Bihar and Odisha have made good progress in improving micronutrient intake through diverse diets, though states like Rajasthan have only seen minor changes. The rise in dietary diversity, especially for the poorest 20%, shows that better infrastructure, transport, and storage have made items like fruits, milk, eggs, and meat more accessible and affordable.



# NMC Withdraws Guidelines About Sodomy, Lesbianism As Unnatural Sexual Offences

►NMC will release the revised guidelines under Competency Based Medical Education Curriculum in due course.

New Delhi.The National Medical Commission on Thursday withdrew and cancelled guidelines under the Competency Based Medical Education Curriculum in which it had reintroduced sodomy and lesbianism as unnatural sexual offences in the forensic medicine and toxicology curriculum for undergraduate medical students. The guidelines were issued on August 31.“It is informed that the Circular of even number dated 31.08.2024 thereby issuing Guidelines under Competency Based Medical Education Curriculum (CBME) 2024, stands “withdrawn and cancelled” with immediate effect. The above guidelines will be revised and uploaded in due course,” the National Medical Commission



(NMC) said. Besides sodomy and lesbianism, the NMC had brought back topics such as the hymen and its type, and its

medico-legal importance in addition to defining virginity and defloration, legitimacy and its medico-legal importance. These subjects were done away with in 2022 in accordance with a Madras High Court directive.The revised curriculum under forensic medicine and toxicology also includes “Describe legal competencies including Bharatiya Nagarika Suraksha Sanhita (BNSS), Bharatiya Nyay Sanhita (BNS), Bharatiya Sakshya Adhiniyam (BSA)” besides “Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO), Civil and Criminal Cases, Inquest (Police Inquest and Magistrate’s Inquest), and cognisable and non-cognisable offences”.It talks about discussing sexual perversions, fetishism, transvestism, voyeurism,

sadism, necrophagia, masochism, exhibitionism, frotteurism and necrophilia. However, distinctions between consensual sex between queer individuals have been removed,a source said. The amended curriculum has done away with the seven-hour training on disability.At the end of teaching-learning in forensic medicine and toxicology, the student should be able to understand the medico-legal framework of medical practice, codes of conduct, medical ethics, professional misconduct and medical negligence, conducting medico-legal examination and documentation of various medico-legal cases and understand latest Acts and laws related to medical professional including related court judgments, the NMC said in its document.

## Congress's fresh charge on Sebi chief: Got rent income from company under probe

Congress's Pawan Khera alleged that Madhabi Buch gave one of her properties on rent to a Mumbai company whose affiliated firm was under probe by Sebi.



New Delhi. Intensifying its attack on Sebi chairperson Madhabi Puri Buch, the Congress on Friday alleged she received rental income from an entity affiliated with a Mumbai company that the markets' regulator was investigating for various cases, including that of insider trading. Addressing a press conference, Congress leader Pawan Khera said, "This is not just conflict of interest, but a case of out-and-out corruption. Is it ethical, is it legal?" Khera alleged that Buch gave one of her properties for rent in Mumbai in 2018-19 to Carol Info Services Ltd for Rs 7 lakh. Then, Buch was a full-time member of Sebi. He said that Carol Info Services Ltd was affiliated to Wockhardt Limited, which is being investigated by Sebi in several cases, including one of insider trading. The Congress leader claimed that Madhabi Buch received Rs 2.16 crore from Carol Info Services Ltd as rent from 2018-19 to 2023-24.

## Naveen Patnaik's party expels Rajya Sabha MP for 'anti-party activities'

Biju Janata Dal (BJD) on Friday announced that the party has expelled its Rajya Sabha MP Sujeet Kumar for 'anti-party activities'.



New Delhi. Biju Janata Dal (BJD) on Friday expelled its Rajya Sabha MP Sujeet Kumar for ‘anti-party activities’, after he resigned from the Upper House earlier today. "Shri Sujeet Kumar, MP, Rajya Sabha representing Biju Janata Dal is expelled from the Party with immediate effect for anti-party activities," former Odisha Chief Minister and BJD president Naveen Pztaaik said in a statement. Patnaik added, "He has let down the Party which sent him to Rajya Sabha and hopes and aspirations of people of Kalahandi district". In his resignation letter to the Rajya Sabha chairman, Kumar said he took the decision “consciously”. His resignation has been accepted by Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankhar with immediate effect. “I take this oppostiuinity to express my profuse gratitude to you for the opportunities provided to me to raise issues of public importance, and of my state Odisha, in the House,” the resignation letter reads. Kumar's resignation comes a month after another BJD member, Mamata Mohanta, resigned from both the Rajya Sabha and the BJD. She was later elected unopposed to the Upper House as a BJP MP.

## Chinks in INDIA bloc? AAP's Delhi MLA joins Congress

Rajendra Pal Gautam, a prominent Dalit leader and MLA from Delhi's Seemapuri, joined the Congress today. The development comes amid ongoing alliance talks between the AAP and Congress for the upcoming Haryana assembly polls.

New Delhi. In a setback to the Aam Aadmi Party (AAP), former Delhi cabinet minister Rajendra Pal Gautam joined the Congress on Friday.Gautam, a prominent Dalit leader and MLA from Seemapuri, joined the Congress in the presence of party leaders KC Venugopal, Devender Yadav, and Pawan Khera. The development comes amid ongoing alliance talks between the AAP and Congress, both members of the INDIA bloc, for the upcoming Haryana assembly polls. Gautam's switch is also a significant gain for the Congress in Delhi, as the Grand Old Party looks to reclaim its lost voter base ahead of Assembly elections in the national capital next year. WHO IS RAJENDRAPAL GAUTAM? A lawyer by profession, Rajendra Pal Gautam joined AAP in 2014 and was elected as an MLA from the Seemapuri constituency in the 2020 Delhi



Assembly polls. Gautam's political career has been marked by his activism for Dalit rights. He was a key figure in the AAP government, holding various portfolios including Social Welfare, SC & ST, Water and Cooperative Societies. In October 2022, Gautam resigned as a cabinet minister in the Delhi government after facing criticism for attending a mass conversion event where around 10,000 people converted to Buddhism. The BJP had accused him of "insulting

Hindu Gods and Goddesses" and demanded his removal by Chief Minister Arvind Kejriwal. Gautam had apologised and shared his resignation letter on social media. The Delhi Congress had accused the AAP government of being "anti-Dalit" and maintained a supportive stance towards Gautam, criticising the ruling party for seeking his resignation.Gautam's departure from the AAP is the third high-profile exit from the party in recent times, following the exit of MLA Kartar Singh Tanwar and ex-Minister Raaj Kumar Anand. This series of defections may weaken the AAP's position ahead of the crucial Delhi Assembly elections. The Congress, on the other hand, has gained a prominent Dalit leader, which could bolster its support among the community.

## Supreme Court Issues Notice On 65% Bihar Quota, No Stay On High Court Order

New Delhi: The Supreme Court on Friday issued a notice to the Centre and the Bihar government on a petition challenging the High Court's order striking down a hike in reservation in Bihar to 65%, but has not imposed a stay for now. The Rashtriya Janata Dal, which is the principal opposition party in Bihar, had moved the top court against the Bihar High Court's verdict on the increased reservation, legislation for which was passed after a caste survey last year. Reacting to the developments in the Supreme Court, the RJD said it will continue to fight for reservation and the "rights of the

deprived". "Supreme Court issues notice on RJD's petition against Patna HC order quashing Bihar Reservation Amendment Act. RJD will keep fighting for the reservation and rights of the deprived and the neglected on the streets, in the House and in the courts," the party wrote in Hindi in a post on X while also hitting out at Bihar Chief Minister Nitish Kumar and the BJP. The quota was increased from 50% to 65% for Backward Classes, Extremely Backward Classes, Scheduled Castes (SCs), and Scheduled Tribes (STs) through amendments to the reservation laws. The bills proposing

the amendments were passed unanimously in the Bihar Assembly and legislative council and the hike in reservation was meant to apply to educational institutions as well as government jobs in the state. After petitioners approached it challenging the constitutional validity of the amendments, the High Court had ruled on June 20 that they were "ultra vires" of the Constitution, "bad in law" and "violative of the equality clause". The bench said it saw "no extenuating circumstance enabling the state to breach" the 50% cap on reservations laid down by the Supreme Court in the Indra Sawhney case of 1992.

## Congress, Sharad Pawar's NCP Name LGBTQ Activists For Key Posts

This follows Congress's poll promise to bring in a law to legalise civil unions between same-sex couples.

New Delhi: The Congress this week set up a new internal group to promote LGBTQ rights while Nationalist Congress Party - Sharadchandra Pawar has named a person from the community as its spokesperson, in the first such political recognition after many setbacks.The Supreme Court in 2018 decriminalised homosexuality but greatly disappointed the LGBTQ community last year when it declined to legalise same-sex marriage and left it to parliament to decide.The central government has also said the legislature is the right platform to rule on the contentious issue, and this week invited the public to share views on how best to ensure that policies for the community are inclusive and effective.

Same-sex relations are mostly taboo and the government told the Supreme Court last year that such marriages were not "comparable with the Indian family unit concept of a husband, a wife and children". Congress, whose political clout has risen after doing much better than expected in the April-June general election, this week named LGBTQ activist Mario da Penha as the head of its new unit for the community under its All India Professionals' Congress division. This follows Congress's poll promise to bring in a law to legalise civil unions between same-sex couples.Da Penha said on X it was the "only representative framework for queer people within any recognised national political party in India".Anish Gawande, who last month

became the first person from the community to become the spokesperson for the opposition Nationalist Congress Party - Sharadchandra Pawar, said da Penha's appointment was "a major moment for queer inclusion in Indian politics". Gawande earlier said on social media of the Nationalist Congress appointment: "If



you'd told me ten years ago that it would be possible to be out and in Indian politics, I would have scoffed in disbelief."The central government says it has taken a host of measures for the community, which includes enabling same-sex couples to access government food programmes as families, open joint bank accounts and choose each other as nominees, and seek medical and other care without discrimination. The Department of Social Justice and Empowerment said in a statement on Sunday it had invited inputs from the public to ensure that policies and initiatives for the community are inclusive and effective.It did not mention any law to recognise marriages between same-sex couples.A spokesperson for the ministry did not immediately respond to a request for comment.

## With Vinesh Phogat Set To Join Congress, Cousin Babita Phogat Has A Message



New Delhi. Former wrestler and BJP leader Babita Phogat on Thursday said how the "party is bigger than the individual and the country supersedes everything", amidst reports that fellow wrestlers Vinesh Phogat, who is her cousin, and Bajrang Punia are set to join the Congress ahead of the Haryana Assembly elections. "Party is bigger than the individual and country is bigger than the party. This is my party's message to everyone! I stand by the decision of the top leadership of my Bharatiya Janata Party. Being a dedicated party worker, I will continue to discharge all the responsibilities given by the organisation," Babita Phogat, who has not figured among the party candidates for the October 5 polls, said in a post on X. Babita Phogat also expressed gratitude to the people of her constituency Charkhi Dadri, saying: "People who always gave me their infinite love and blessings like their daughter and sister. I will always be ready to serve you in the future as well. Jai Hind, Jai Bharat." According to reports, Olympians Vinesh Phogat and Punia will be joining the Congress on Friday, ahead of the Haryana Assembly elections. It is expected that Vinesh Phogat will contest the election from Haryana's Julana seat which is held by the Jannayak Janta Party's Amarjeet Dhandha. The development comes mere days after the two wrestlers met with the party's leader, Rahul Gandhi on September 4. Bajrang Punia and Vinesh Phogat, along with Sakshi Malik, were among the wrestlers who protested against then BJP MP and Wrestling Federation of India President Brij Bhushan Sharan Singh, for allegedly intimidating and sexually harassing several women wrestlers. This issue is said to have resonated during the Lok Sabha elections and is likely to be a key issue in the Haryana Assembly polls.



News box

Joe Biden's son Hunter pleads guilty in \$1.4 million tax evasion case

**World** Hunter Biden, son of U.S. President Joe Biden, pleaded guilty to federal tax charges on Thursday, a surprise move that avoids a potentially embarrassing trial weeks before the U.S. presidential election.Biden had been set to stand trial in a Los Angeles federal courthouse on criminal charges of failing to pay \$1.4 million in taxes while spending lavishly on drugs, sex workers and luxury items.Judge Mark Scarsi told Biden he faces up to 17 years in prison and up to \$450,000 in penalties. He set sentencing for December 16. Defendants who plead guilty in criminal cases typically work out an agreement with prosecutors beforehand, hoping to receive a lower sentence in exchange for avoiding trial. That did not appear to be the case here. Earlier in the day, Biden had offered to plead guilty to the charges but avoid admitting wrongdoing, an unusual legal manoeuvre called an "Alford plea." Prosecutors opposed that move.After a break, Biden's lawyer, Abbe Lowell, told the judge that he would plead guilty, despite having no prior agreement with prosecutors that would ease his sentence.In a statement after the hearing, Biden said he pleaded guilty to spare his family from having to sit through a trial that would have aired messy details from a period of his life where he was suffering from drug addiction. "For all I have put them through over the years, I can spare them this," he said. He added that he had paid back his taxes.Lowell told reporters afterward that Biden might appeal his sentence. He did not answer when asked why Biden waited until the trial's opening day to plead guilty.

Bangladesh: Hindu boy accused of blasphemy, thrashed by mob inside police station

**New Delhi** A 15-year-old Hindu boy named Utsav Mondal was brutally beaten by a mob inside a police station in Bangladesh after he was accused of making derogatory remarks about the Prophet Muhammad on social media. The incident took place on Wednesday night in the Sonadanga residential area of Khulna. Local media reports initially suggested that Mondal had succumbed to his injuries, but Khulna Metropolitan Police's Deputy Commissioner (South), Mohammad Tajul Islam, later confirmed to India Today that the teenager is alive and receiving treatment. He is admitted to an army hospital and is out of danger," Islam said.The incident occurred around 11:45 PM when a group of local madrasa students brought Utsav to the police station, accusing him of posting "objectionable comments" on Facebook about the Prophet.Tensions escalated quickly as more students and members of the Imam Association gathered outside the police station, demanding immediate and severe punishment for the boy.Mohammad Tajul Islam recounted the sequence of events, stating that initially, the students demanded that Utsav be judged according to their own laws, which involved execution. The deputy commissioner assured them that a case would be filed under existing laws, but this did not satisfy the crowd. The situation turned volatile as the number of protestors swelled to nearly thousand by evening, creating a highly charged atmosphere outside the police station.

China's Xi promises \$50 billion for Africa over next three years

**BEIJING.** Chinese leader Xi Jinping pledged on Thursday more than \$50 billion in financing for Africa over the next three years, promising to deepen cooperation in infrastructure and trade with the continent as he addressed Beijing's biggest summit since the Covid pandemic.More than 50 African leaders and UN Secretary-General Antonio Guterres are attending the China-Africa forum, according to state media.African leaders already secured a plethora of deals this week for greater cooperation in infrastructure, agriculture, mining, trade and energy.Xi hailed ties with Africa as their "best period in history" as he addressed the leaders at the forum's opening ceremony in Beijing's ornate Great Hall of the People on Thursday. "China is ready to deepen cooperation with African countries in industry, agriculture, infrastructure, trade and investment," he said. "Over the next three years, the Chinese government is willing to provide financial support amounting to 360 billion yuan (\$50.7 billion)," Xi said.More than half of that will be in credit, he said, with \$11 billion "in various types of assistance" as well as \$10 billion through encouraging Chinese firms to invest. He also promised to help "create at least one million jobs for Africa".Xi pledged \$141 million in grants for military assistance, saying Beijing would "provide training for 6,000 military personnel and 1,000 police and law enforcement officers from Africa".Guterres told the forum that growing ties between China and Africa could "drive the renewable energy revolution". "China's remarkable record of development -- including on eradicating poverty -- provides a wealth of experience and expertise," he said. Chinese foreign minister Wang Yi hailed the summit as a "complete success" at a joint news conference with his Senegalese and Congolese counterparts later on Thursday.

Brazilian court orders two slaughterhouses to pay for Amazon reforestation

A court in Brazil has convicted two beef slaughterhouses guilty of buying cattle from a protected area and directed them to pay \$764,000 for causing environmental damage and reforestation of the Amazon forest.

**Brasilia** A judge in the Brazilian state of Rondonia has found two beef slaughterhouses guilty of buying cattle from a protected area of former rainforest in the Amazon and ordered them, along with three cattle ranchers, to pay a total of \$764,000 for causing environmental damage, according to the decision issued Wednesday. Cattle raising drives Amazon deforestation. The companies Distriboi and Frigon and the ranchers may appeal.It is the first decision in several dozen lawsuits seeking millions of dollars in environmental damages from the slaughterhouses for allegedly trading in cattle raised illegally in a protected area known as Jaci-Parana, which was rainforest but is now mostly converted to pasture.Four slaughterhouses are among the many parties charged, including JBS SA, which bills itself as the world's largest protein producer. The court has not decided on the cases involving JBS.Brazilian law forbids commercial cattle inside a protected area, yet some 210,000

head are being grazed inside Jaci-Parana, according to the state animal division. With almost 80 per cent of its forest destroyed, it ranks as the most ravaged conservation unit in the Brazilian Amazon. A court filing pegs damages in the reserve at some \$1 billion.

The lawsuits are based on transfer documents first reported by the Associated Press that show cattle going directly from protected areas to slaughterhouses. The documents were filled out by the illegal ranchers themselves.Part of the decision is a collective penalty of \$453,000 against the five defendants, who are linked to one farm. The money will be used to reforest 232 hectares (573 acres) of what is now pasture there.“When a slaughterhouse, whether by negligence or intent, buys and resells



products from invaded and illegally deforested reserves, it is clear that it is directly benefiting from these illegal activities,” according to a part of the original complaint which Judge In's Moreira da Costa sustained in her ruling. “In such cases, there is an undeniable connection between

the company’s actions and the environmental damage caused by the illegal exploitation.”Frigon and Distriboi did not respond to questions sent by email. In a filing, Frigon argued the state of Rondonia allowed ranchers to sell the cattle and said there is no relation between buying beef cattle and deforestation. In filings, Distriboi also denies any wrongdoing. JBS also did not reply to a request for comment.

Rondonia, on the border with Bolivia, is the most badly deforested state in the Brazilian Amazon. In the past few weeks, most cities have been covered by thick smoke from wildfires, a sign of rampant deforestation. The situation is so dire that its main airport in Porto Velho was closed for seven consecutive days.

Father of US teen who killed 4 in Georgia school shooting arrested

**World** Georgia state officials arrested the father of the 14-year-old suspected school shooter Colt Gray on Thursday in connection with Wednesday's shooting that killed four people and wounded nine at Apalachee High School.Colin Gray, 54, was charged with four counts of involuntary manslaughter, two counts of second-degree murder and eight counts of cruelty to children, the Georgia Bureau of Investigation said."These charges stem from Mr. Gray knowingly allowing his son Colt to possess a weapon," Chris Hosey, director of the Georgia Bureau of Investigation, told a media conference.Colt Gray has been charged with four counts of felony murder and would be tried as an adult, officials said.

Both Grays had been questioned by local officials in neighbouring Jackson County last year in connection with an online threat to commit a school shooting, but there was no probable cause for their arrest, the FBI said on Wednesday. In that 2023 probe, the father said he had hunting guns in the house but that his son did not have unsupervised access to them, and the son denied making the threats online, the FBI said. Georgia state and Barrow County investigators say the younger Gray used an "AR platform style weapon," or semi-automatic rifle, to carry out the attack in which two teachers and two 14-year-old students were killed.It remained unclear how the shooter obtained the weapon.Investigators have yet to comment on what may have motivated the first U.S. campus mass shooting since the start of the school year.Jackson County sheriff's investigators closed the case after being unable to substantiate that either Gray was connected to the Discord account where the threats were made, and did not find grounds to seek the needed court order to confiscate the family's guns, according to police reports released by the sheriff's office on Thursday. "This case was worked, and at the time the boy was 13, and it wasn't enough to substantiate.



**Phoenix.** Republican vice presidential nominee JD Vance said Thursday that he lamented that school shootings are a “fact of life” and argued the US needs to harden security to prevent more carnage like the shooting this week that left four dead in Georgia.“If these psychos are going to go after our kids we’ve got to be prepared for it,” Vance said at a rally in Phoenix. “We don’t have to like the reality that we live in, but it is the reality we live in. We’ve got to deal with it.”The Ohio senator was asked by a journalist what can be done to stop school shootings. He said further restricting access to guns, as many Democrats advocate, won’t end them, noting they happen in states with both lax and strict gun laws. He touted efforts in Congress to give schools more money for

security.“I don’t like that this is a fact of life,” Vance said. “But if you are a psycho and you want to make headlines, you realise that our schools are soft targets. And we have got to bolster security at our schools. We’ve got to bolster security so if a psycho wants to walk through the front door and kill a bunch of children they’re not able.”He called the shooting in

Georgia an “awful tragedy,” and said the families in Winder, Georgia, need prayers and sympathy.Earlier this year, Vice President Kamala Harris, the Democratic presidential nominee, toured the bloodstained Florida classroom building where the 2018 Parkland high school massacre happened. She then announced a program to assist states that have laws allowing police to temporarily seize guns from people judges have found to be dangerous.Harris, who leads the new White House Office of Gun Violence Prevention, has supported both stronger gun controls, such as banning sales of AR-15 and similar rifles, and better school security, like making sure classroom doors don’t lock from the outside as they did in Parkland.

Putin backs Harris for US president, with wry smile

**MOSCOW.** Russian President Vladimir Putin said Thursday he supported Kamala Harris in November's US presidential election, an apparent wry remark that led to a renewed call from Washington for the Kremlin to "stop interfering".Putin was speaking a day after the United States issued indictments accusing Moscow of vote interference. The Kremlin leader frequently comments on political and social issues in the United States, often in a mocking way. He said last year that the US political system was "rotten" and that Washington could not lecture other countries about democracy.US officials have repeatedly warned of efforts by foreign powers to meddle in the upcoming US election, accusing Moscow of seeking to influence US ballots dating back to the 2016

contest between Trump and Democrat Hillary Clinton."Firstly, (US President Joe) Biden recommended all his supporters support Mrs Harris," Putin said during a question and answer session at Russia's Eastern Economic Forum in Vladivostok.Biden withdrew from the race in July amid concerns about his age and health, endorsing Vice President Harris to top the Democratic Party's ticket."Here, we are going to do that too, we're going to support her," Putin told the audience, with a wry smile."She laughs so contagiously that it shows that everything is fine with her," the Russian leader said.(Former US President Donald) Trump has imposed as many sanctions on Russia as any president has ever imposed before, and if Harris is doing well, perhaps she will refrain from

such actions." Responding to Putin's comments, National Security Council spokesman John Kirby on Thursday urged the Russian leader to "stop interfering" in US elections. "The only people who should get to determine who the next president of United States is are the American people, and we would greatly appreciate it if Mr. Putin would, a) stop talking about our election, and b) stop interfering in it," he said.In February, Putin backed Biden over Trump, calling the current president more "predictable". The White House called on Putin to "stay out" of US elections in response.Trump has said he will end the Ukraine conflict within "24 hours" if he is re-elected and has praised Putin as a "very smart cookie" who had repeatedly outsmarted the United States.

Singapore jails Gurkha Contingent officers for running unlawful cross-border money transfer services

Deputy Public Prosecutor (DPP) Brian Tan told the court that sometime in or before June 2021, Pratik began offering a money remittance service to the other GC officers within their camp.

**SINGAPORE.** Five officers from the Gurkha Contingent (GC), Singapore's most trusted police force division, were sentenced to jail terms after they pleaded guilty to operating unlawful cross-border money transfer services, with each man's case involving transactions between SGD 1,03,473 and SGD 2.86 million.They were given jail sentences on Thursday after they pleaded guilty to charges under the Payment Services Act (PSA), The Straits Times reported.The Gurkha officers from a special unit of the police force are deployed in sensitive areas here. Officer Sitaram Tamang's case involved over SGD 2.86 million in total and he was sentenced to five months in jail. The 40-year-old had pleaded guilty to a charge under the PSA involving nearly SGD 1.6 million. Three other charges were also considered during sentencing.Dik Bahadur Gurung, 32, was sentenced to 14 weeks in jail after he pleaded guilty to two

charges relating to more than SGD 1 million in total.Ganga Prasad Rai, 43, pleaded guilty to two charges involving more than SGD 6,00,000 and was sentenced to 10 weeks in jail.Ashok Kumar Thapa Magar, 39, and Mingmar Sherpa, 44, pleaded guilty to one charge each under the PSA.Mingmar's case involved nearly SGD 4,72,000, and he was sentenced to seven weeks in jail, while Ashok, whose case was linked to more than SGD 1,03,000, was ordered to spend four weeks behind bars.The prosecution said that a sixth man, Pratik Tamang, 41, is linked to some of the charges.He joined the GC in 2004 and returned to Nepal in February 2022 after his retirement.He is still at large, according to the Strait Times.Deputy Public Prosecutor (DPP) Brian Tan told the court that sometime in or before June 2021, Pratik began offering a money remittance service to the other GC officers within their



camp.According to court documents, he later recruited Ganga and Dik to work with him.He also engaged Sitaram to help him collect the money.Pratik was already in Nepal when Sitaram worked with him between February and July 2022 to provide an unlawful payment service in Singapore.DPP Tan said, "Under the arrangement, GC officers looking to remit money from Singapore dollars to Nepalese rupees (NPR) from Singapore to Nepal would contact Pratik via his

mobile number."After informing Pratik of the amount in dollars that they were looking to remit, Pratik would first transfer the equivalent amount in NPR to the remitters' beneficiaries in Nepal."He would then ask the remitters to contact Sitaram in Singapore to transfer the equivalent value in dollars to Sitaram's bank account linked to the payment platform PayNow.Nearly USD 1.6 million involving 111 deposits went through the bank account.After that, Sitaram would arrange to hand over the remittance monies in dollars to Pratik, either by PayNow transfers to the latter's bank account or in cash to Pratik's friends.Between February and July 2022, Ganga engaged in a conspiracy with Sitaram and Pratik to offer a cross-border money transfer service.Ganga then collected more than SGD 2,43,000, which he handed over to Sitaram.

Feeling the heat as Earth breaks yet another record for hottest summer

The northern meteorological summer — June, July and August — averaged 16.8 degrees Celsius (62.24 degrees Fahrenheit), according to Copernicus. That's 0.03 degrees Celsius (0.05 degrees Fahrenheit) warmer than the old record in 2023.

**World** Summer 2024 sweltered to Earth's hottest on record, making it even more likely that this year will end up as the warmest humanity has measured, European climate service Copernicus reported Friday.And if this sounds familiar, that's because the records the globe shattered were set just last year as human-caused climate change, with a temporary boost from an El Nino, keeps dialing up temperatures and extreme weather,

scientists said. The northern meteorological summer — June, July and August — averaged 16.8 degrees Celsius (62.24 degrees Fahrenheit), according to Copernicus. That's 0.03 degrees Celsius (0.05 degrees Fahrenheit) warmer than the old record in 2023. Copernicus records go back to 1940, but American, British and Japanese records, which start in the mid-19th century, show the last decade has been the hottest since regular measurements were taken and likely in about 120,000 years, according to some scientists.The Augusts of both 2024 and 2023 tied for the hottest Augusts globally at 16.82 degrees Celsius (62.27 degrees Fahrenheit). July was the first time in more than a year that the world did not set a record, a tad behind 2023, but because June 2024 was so much hotter than June 2023, this

summer as a whole was the hottest, Copernicus Director Carlo Buontempo said. “What those sober numbers indicate is how the climate crisis is tightening its grip on us,” said Stefan Rahmstorf, a climate scientist at the Potsdam Institute for Climate Research, who wasn’t part of the research. It’s a sweaty grip because with the high temperatures, the dew point — one of several ways to measure the air’s humidity — probably was at or near record high this summer for much of the world, Buontempo said.Until last month Buontempo, like some other climate scientists, was on the fence over whether 2024 would smash the hottest year record set last year, mostly because August 2023 was so enormously hotter than average. But then this August 2024 matched 2023, making Buontempo “pretty certain” that this year will end up hottest on

record.“In order for 2024 not to become the warmest on record, we need to see very significant landscape cooling for the remaining few months, which doesn’t look likely at this stage,” Buontempo said. With a forecasted La Nina — a temporary natural cooling of parts of the central Pacific — the last four months of the year may no longer be record-setters like most of the past year and a half. But it’s not likely cool enough to keep 2024 from breaking the annual record, Buontempo said. These aren’t just numbers in a record book, but weather that hurts people, climate scientists said.“This all translates to more misery around the world as places like Phoenix start to feel like a barbecue locked on high for longer and longer stretches of the year,” said University of Michigan environment dean and climate scientist Jonathan Overpeck.





NEWS BOX

## US Open: Aryna Sabalenka ready for Final after 'missed opportunity' last year

Aryna Sabalenka is determined to make the most of her second consecutive US Open final appearance after narrowly missing out on the title last year. The Belarusian tennis star revealed her resolve to "give it her all" in the upcoming final, reflecting on last year's disappointment where she lost to Coco Gauff despite winning the first set. Sabalenka secured her spot in the 2024 US Open final by defeating USA's Emma Navarro 6-3, 7-6 (7-2) on September 5 at the Arthur Ashe Stadium in a thrilling semi-final clash. In her post-match press conference, Sabalenka expressed her eagerness to make amends for last year's heartbreak and finally clinch the hard-court major. She emphasized her readiness to put everything on the line in what promises to be a high-stakes final. Sabalenka's road to the final was marked by her powerful and consistent play, which was on full display against Navarro. The Belarusian, known for her aggressive baseline game, managed to keep the pressure on Navarro throughout the match, particularly in the second-set tiebreak where she dominated to secure her place in the final. "Yeah, I had really tough lessons here in the past," I think I had so many opportunities here, but I didn't use them for different reasons. I wasn't ready. Then I got emotional. Then I just couldn't handle the crowd. I felt like I just missed the opportunity. Every time I'm coming back here, I have this positive thinking, like, 'Come, on, maybe this time'," Sabalenka said. "Every time I'm hoping that one day I'll be able to hold that beautiful trophy. You know, like tough losses never make me feel depressed, like, not thinking like of not coming back on the tournament. It only motivates me to come back and to try one more time, try harder, and work harder on some things which maybe didn't work in the past. I'm still hoping to hold that beautiful trophy," Sabalenka added. In the final, Sabalenka will face Jessica Pegula, who earned her spot by defeating the world number one, Iga Swiatek, in their semi-final clash. With Pegula being the home star, Sabalenka also revealed that she is not worried to face the Arthur Ashe crowd going against her in the final. "Yeah, they're cheering for her, but how can they help her to win the match? Only if I let them get into my head and only if I'm gonna just lose myself, you know, get crazy... So, yeah, that's the trickiest is the loudness of how loud it can be on this stadium,"

## Harshit Rana's 'flying kiss' celebration returns after Gaikwad's wicket

**New Delhi** Indian pacer Harshit Rana's iconic flying kiss celebration made a return on Day 1 of the Duleep Trophy tournament. His infamous send-off has been the talking point since IPL 2024 and Harshit brought it back again. Harshit, while playing for India D, got the wicket of India C captain Ruturaj Gaikwad. During the 7th over of India C's first innings, Harshit bowled a short of length delivery outside the stumps and Gaikwad edged it only to be caught at the slips. India D erupted in celebrations and Harshit Rana gave his infamous 'flying kiss' gesture. However, this time it was not directed towards the batter he dismissed but to the dressing room.

Gaikwad managed to score just five runs in 19 balls in his short stay at the crease. Earlier, Harshit also dismissed opening batter Sai



Sudharsan for just seven runs from 16 balls. Harshit provided his team just the kind of start which they needed as India C were reduced to 14/2 in first seven overs. Interestingly, Harshit's flying kiss celebration caught everyone's attention during the IPL 2024 when he was representing KKR.

### Harshit's flying kiss celebration

When Harshit faced ban for his send-off

He gave a flying kiss send-off to Mayank Agarwal after dismissing him during KKR vs SRH match on March 23. Later, the KKR fast bowler Harshit Rana was suspended for a match and fined 100 percent of his match fee for breaching the IPL Code of Conduct for the second time in the IPL 2024 season. Harshit's second offence came during KKR's win against Delhi at Eden Gardens on April 29. He came up with an animated gesture towards DC's Abhishek Porel after getting his wicket. Later, the KKR team's co-owner Shahrukh Khan asked the entire squad to give a flying kiss as part of their celebration on lifting the ICC trophy. Meanwhile, Harshit will be aiming to impress the selectors and offer his contention for the upcoming big home season. He was selected in the T20I squad for Zimbabwe and ODI squad for the Sri Lanka series.

# Pickleball Boom: The trendy, social sport is winning hearts in India too

**Pickleball is booming worldwide, and India is no exception. Once played in parking lots and alleys, it's now entering the professional era. Pioneers Sunil Valavakar and Manish Rao, in conversation with IndiaToday.in, highlight the sport's rapid growth and its ability to transcend age groups and make a meaningful impact on enthusiasts' lives.**

**New Delhi.** Ajit Pal Singh, a software engineer from Noida, first discovered pickleball through an Instagram reel. The clip showed a game that looked like a mix of tennis and badminton, piquing his curiosity. A quick Google search later, he was hooked. Six months on, Singh and three friends became regulars at a popular pickleball centre in Noida, playing almost every weekend. For early pioneers like Sunil Valavalkar and Manish Rao, spreading the word about pickleball in India was a challenge. But today, the game is rapidly capturing the attention of urban India, drawing in players aged eight to 80. It's hard to escape the growing popularity of pickleball. You must

have seen Andre Agassi or Leonardo Di Caprio playing pickleball. Even Novak Djokovic, who once hinted that pickleball posed a threat to tennis, was seen trying his hand at the sport at an exhibition event before the 2023 US Open. In India, the sport has found fans in Bollywood actors and sports icons alike. It's no surprise: pickleball is among the fastest-growing sports worldwide, and India is no exception. Rajat, a 23-year-old finance professional, was introduced to the sport by Singh. He now makes a 50km trip from Gurugram to Noida every weekend to play. "It's less strenuous than tennis and a bit different from badminton," Rajat says. "The sound of the paddle hitting the ball reminds me of cricket. As a cricket lover, I enjoy it a lot. It's become a weekly affair." Pickleball's simple learning curve, social nature, and low physical impact have contributed to its widespread popularity. Its accessibility makes it appealing across age groups, and it's being embraced both recreationally and competitively.

### A PANDEMIC BOOM

The pandemic provided an unexpected boost for pickleball. It proved to be a "blessing in disguise" for the sport. People gravitated to the sport during lockdowns due to its ease of setup and suitability for socially distanced play. It became a common sight in alleys and parking lots across cities.

In the United States of America, pickleball



surged so much that tennis courts were repurposed for it, as four pickleball courts can fit into one tennis court. More courts meant more players and more revenue, catching the attention of investors and sports equipment manufacturers like Selkirk, which started sponsoring players.

India saw a similar boom after the pandemic. A pickleball tournament with prize money worth USD 100,000 was held as recently as August 2024. India has been hosting major tournaments and Indian pickleball players have begun to win medals in prestigious overseas competitions. An Indian Premier League-styled league for pickleball is also set to start by the end of 2024 or early 2025.

### THE BASICS OF PICKLEBALL

#### 1. Pickleball Equipment

**Paddle:** A solid paddle, larger than a ping-pong paddle but smaller than a tennis racket, made of wood, composite, or graphite.

**Ball:** A lightweight plastic ball with holes, similar to a wiffle ball, which travels slower

## PM Modi praises Kapil Parmar for 'special' Paralympics Judo bronze medal

**Prime Minister Narendra Modi hailed Kapil Parmar's historic bronze medal in Judo at the Paris Paralympics, marking India's first-ever Judo Paralympic medal and celebrating the inspiring journey of the visually impaired para-athlete from Madhya Pradesh.**

**New Delhi.** Prime Minister Narendra Modi extended heartfelt congratulations to Kapil Parmar on his remarkable bronze medal victory in Judo at the Paris Paralympics. In a special post on his official X account, PM Modi hailed Parmar's achievement as a "special medal" win for India, celebrating his historic accomplishment as the first-ever Judo medalist for the country at the



Paralympics.

The 24-year-old visually impaired para-athlete from Shivori, Madhya Pradesh, secured the bronze in the men's -60kg J1 category by defeating Brazil's Elielton de Oliveira in just 33 seconds with a stunning Ippon. Parmar's victory is a significant milestone, raising India's medal tally at the Games to 25, including five gold, nine silver, and 11 bronze medals. "A very memorable sporting performance and a special medal!"

Congratulations to Kapil Parmar, as he becomes the first-ever Indian to win a medal in Judo at the Paralympics. Congrats to him for winning a Bronze in the Men's 60kg J1 event at the #Paralympics2024! Best wishes for his endeavours ahead," Parmar, who had already made a name for himself by winning a silver medal in the same category at the 2022 Asian Games, showcased his prowess by defeating Venezuela's Marco Dennis Blanco 10-0 in the quarterfinals. His journey to the Paralympics was not without challenges. As a child, Parmar suffered a severe electric shock after accidentally touching a water pump while playing in the fields, leaving him in a coma for six months.

Despite this life-altering experience, Parmar's triumph at Paris turns out to be one of the key highlights of India's Paralympics 2024 campaign.

## Vikram Rathour, Rangana Herath to help New Zealand prepare for Test season in Asia

**New Delhi** Former India batting coach Vikram Rathour and legendary Sri Lanka spinner Rangana Herath have joined New Zealand team to help them prepare for their upcoming Tests in Asia. Notably, New Zealand will take on Afghanistan in a one-off Test from September 9 in Greater Noida, India and will further lock horns with Sri Lanka and India for five Tests. Ahead of a crucial Test season in Asia, New Zealand Cricket have secured the services of Rathour and Herath to help them succeed in the alien conditions. Rathour, who was recently part of the Indian coaching staff as batting coach under Rahul Dravid, will be with the team for the one-off Test against Afghanistan. On the other hand, Herath will be with the team till the two-match series against Sri Lanka beginning from 18th September. The former left-arm spinner has joined the team in place of former Pakistan spinner and coach Saqlain Mushtaq, who was expected to take up the role earlier but pulled out to take up a position with the Pakistan Cricket Board (PCB). New Zealand Head Coach Gary Stead expressed excitement on the joining



of the two new members and said that both will add on to the knowledge and skill set of the team. "We're really excited to introduce Rangana and Vikram into our Test group. Both men are held in high regard in the world of cricket and I know our players are really looking forward to the opportunity to learn from them," said Stead in a media release. Stead banking on Herath's

experience to succeed in Sri Lanka. Further speaking ahead, Stead mentioned how Herath's influence will massively help their left-arm spinners Ajaz Patel, Rachin Ravindra and Mitchell Santner in the Sri Lanka series. "For our three left-arm orthodox spinners in particular, Ajaz, Mitch and Rachin, having the chance to work with Rangana across three Tests on the sub-continent will be hugely beneficial. Rangana has taken over 100 Test wickets in Galle which is the venue of our two Tests against Sri Lanka and so his knowledge of that venue will be priceless," he added. Meanwhile, New Zealand are currently ranked on the third spot in the World Test Championship standings with three wins from six matches having a points percentage of 50%. The upcoming Tests against Sri Lanka and India are extremely crucial for the Blackcaps to climb higher on the table or maintain their position.

# Duleep Trophy: Anantapur stadium packed, Chinnaswamy stands in Bengaluru empty

**Duleep Trophy: Huge crowd turned up at the Anantapur stadium in Andhra Pradesh for India C vs India D match. Meanwhile, the stands at the M Chinnaswamy Stadium in Bengaluru were empty.**

**New Delhi,** India's much-anticipated domestic season started off on a high with 2 cracker of contests underway between India A-B and India C-D. Day 1 witnessed many notable performances from the Indian players, with Musheer Khan scoring a century and Axar

Patel playing a heroic knock of 86 runs while also picking two wickets. The fans also seemed excited over the start of India's home season. The Duleep Trophy matches will be hosted in Bengaluru and Andhra Pradesh's Anantapur. Hence, M Chinnaswamy Stadium in Bengaluru, Rural Development Trust Stadium and ACA ADCA Ground in Anantapur are the venues of the matches. The Day 2, being Friday, saw huge crowds turning up in stadiums to cheer for the players. However, it was the Rural Development Trust Stadium in Anantapur, which saw fans arriving in huge numbers to fill-up the stands. The Anantapur stadium is hosting the India C vs India D clash with players like Ruturaj Gaikwad, Shreyas Iyer, Axar Patel, Devdutt Padikkal and Arshdeep Singh participating. The fans flocked to the stadium to support the star



players.

### The craze among Anantapur crowd

Meanwhile, the M Chinnaswamy Stadium is hosting India A vs India B with stars like Shubman Gill, Rishabh Pant, Kuldeep Yadav, Yashasvi Jaiswal and Shivam Dube playing. However, there was not as much

than a tennis ball.

**2. Court Dimensions**  
The court measures 20x44 feet, same for singles and doubles.

A 7-foot no-volley zone near the net, called the "kitchen", prevents volleys unless the ball bounces.

**3. Gameplay**  
Objective: Hit the ball over the net into the opponent's court without return. The serve is underhand and must bounce before being returned. The serving team can only score points; games go to 11 points, with a 2-point win requirement.

**4. Serve and Return Rules**  
Double-bounce rule: Both teams must let the ball bounce once after the serve before volleys are allowed.

**PICKLEBALL'S ORIGINS AND ARRIVAL IN INDIA**  
Pickleball originated in Bainbridge Island, Washington, in 1965. Three friends -- Pritchard, Bill Bell, and Barney McCallum-- created the game using makeshift equipment, and it quickly gained local popularity. In India, the credit for introducing pickleball goes to Sunil Valavalkar, the founder of the All India Pickleball Association (AIPA). Valavalkar first encountered the sport when he went to British Columbia as a Project Supervisor for an Indo-Canadian Youth Exchange Program of the Government of India in 1999. There, he was hosted by a sports enthusiast.

## Messi's heartfelt farewell to Angel Di Maria on retirement: We'll miss you a lot

**New Delhi,** Lionel Messi sent a heartfelt farewell message to Angel Di Maria as the Argentine winger announced his international retirement, receiving a moving tribute at the Estadio Más Monumental ahead of Argentina's FIFA World Cup qualifier against Chile. Angel Di Maria called time on his 16-year international journey with Argentina following their Copa America 2024 triumph on July 15. The 36-year-old winger made significant contributions to Argentina across four World Cups (2010, 2014, 2018, and 2022), playing a crucial role in the team that reached the final in Brazil in 2014 and ultimately clinched the World Cup in Qatar 2022. In an emotional tribute video, Messi congratulated Di Maria on his illustrious international career, ending with a touching note that brought tears to Di Maria's eyes.

"I hope you enjoy this evening a lot with your family and loved ones. We've said everything we needed to say... We shared so much, and who would have thought it would



end this way? We'll miss you a lot. See you soon," In Copa America competitions, Di Maria experienced the agony of near victories, finishing as a runner-up in 2015 and 2016, before finally achieving glory in 2021. His decisive goal against Brazil at the Maracanã Stadium secured the long-awaited continental trophy, cementing his status as one of Argentina's most iconic players. During the tribute ceremony, the entire Estadio Mas Monumental erupted in a standing ovation for Di Maria. The players formed a guard of honor for him and his family before lifting him high into the air in celebration. The ceremony featured a video montage with messages from former greats and Messi himself, all acknowledging Di Maria's exceptional career with Argentina.





# Shweta Tiwari

## Unbuttons Her Shirt, Looks Hottest In Pink; New Photos Go Viral

Who would believe that Shweta Tiwari 42 and a mother of three? The actress, popularly known for her role as ‘Perna’ in the hit show Kasautii Zindagii Kay, often drops pictures of herself on social media, leaving everyone stunned. On Thursday too, Shweta took to her Instagram handle and shared a series of photos which are now setting fire online. In these latest photos, Shweta Tiwari was lying on a bed in an unbuttoned pink shirt. She left her tresses open and opted for minimal makeup. The actress’ hot avatar and seducing looks left everyone gasping for breath. Check it out here: Soon after the pictures were shared online, fans rushed to the comments section to compliment the actress. “National crush to yehi hai bhai,” one fan wrote. Stunning you!”

and added another. Those eyes,” a third comment read. Shweta Tiwari became a household name after she was featured in the popular daily soap Kasautii Zindagii Kay. She is also known for shows like Hum Tum and Them, Main Hoon Aparajita, Mere Dad Ki Dulhan, Indian Police Force, Parvarish – Kuchh Khattee Kuchh Meethi and Begusarai among others. Shweta will also be playing the role of an intelligence officer in Ajay Devgn’s Singham Again. Recently, in an exclusive conversation with News18 Showsha, Shweta confirmed that she will soon be collaborating with Karan Johar. She spilled the beans on her next with the filmmaker’s production house and said, “I’m doing Dharma Productions’ upcoming web series. In that, I play a don-like character who wears a saree and smokes cigarettes (laughs). It was a very challenging role and that’s why I wanted to do it.” Though she remained tight-lipped about other details, Shweta shared that she’s ready for smaller roles in this new chapter of her career. “I’ve always told myself – ‘do what you like.’ I’ve been a lead face in television but when I’m stepping out and foraying into something else, I want to explore different parts. I know that I’ve to accept smaller roles if I want to work with a certain director or an actor. I want to make my debut in different avenues every five years,” she added.



### Krushna Abhishek Says His Relationship With Kashmera Started With a 'One Night Stand': 'We Were Not Serious'



When Kashmera Shah marked her 18 years of togetherness with Krushna Abhishek earlier this year, she penned down an emotional note on social media and revealed how a lot of people initially thought that their relationship would not last long. Now, in an interview, Krushna has jokingly revealed that their relationship started only as a ‘one night stand’. Krushna Abhishek was speaking to ETimes when he recalled how happy he was when he started to date Kashmera. “Kash was a hot, sexy and popular actress working with Shah Rukh Khan and Jackie Shroff. I was a newcomer then. The age difference was not important. I connected with her and enjoyed flaunting her as my girlfriend, saying, ‘Dekho main Kashmera Shah ko date kar raha hoon,’” he said. The actor, known for his appearances on Kapil Sharma’s comedy shows, revealed that they first met on a film set in Jaipur. He admitted that they were not serious about each other initially and thought that their dating would not last long. However, things changed with time and they became each other’s best friends. “I first met her on a film set in Jaipur, where we were casually introduced and eventually became friends. One day, she called me to her room for dinner, and that’s how our relationship started... with a one-night stand (laughs). Funnily, the joke we share is how, after that one dinner, I just stayed back with her!” he said. “Initially, we were not serious about each other, we travelled and had a good time for many years. When we started dating, we were not thinking of marriage and felt it would end in a few months. But I was always happy around Kashmera. We are each other’s best friends. People often joke about how Krushna likes two things: Kash and cash!” the actor added.

### When Sobhita Dhulipala Said She 'Looks Forward To Motherhood': 'By Being Coupled You Feel...'



Sobhita Dhulipala has caught everyone’s attention after she recently got engaged to Naga Chaitanya. Fans are eagerly awaiting any news about their wedding. Amid this, an interview with the actress from earlier this year has got fans buzzing. In the interview, Sobhita said that she is looking forward to motherhood next in life. When asked about the meaning of life for her, Sobhita told ABP News, “I don’t think life can have a purpose. I do think that we come between two shores. There is a river, and life is that boat that passes from one shore to another. So I feel like in life, whatever you do, do it and enjoy it, but there is a certain detachment I feel towards everything. I can’t be too detached, because then we won’t have any ambition. But somewhere I walk the tightrope between being a little disconnected and doing my own thing.” “From life, what do I seek? To be honest, I think the experience I look forward to is motherhood, whenever that happens. I feel it would be amazing,” she added. Sobhita also spoke about balancing parenthood and a career. “We don’t pick between taking care of our parents and going for a job. So I feel my role as a daughter and my role as a sister, my role at work as a professional and my role as a wife will work in parallel,” she said. “I feel like even if someone is not very financially secure, very often, by being coupled, you feel like you have a partner who will support you. There are women who do a lot, and there are many stories of men who also support their wives in doing whatever they want to do. So I don’t think it’s this or that. I am very pro-balance. I have things that I’d love to experience, and I love to hit certain goalposts, but my idea of success is not vertical; it’s more horizontal,” the actor added. Naga Chaitanya and Sobhita Dhulipala got engaged last month. The couple was dating for almost two years before they announced their engagement. Making their relationship public, the couple shared a poetic message, quoting, “What could my mother be to yours? What kin is my father to yours anyway? And how did you and I meet ever? But in love our hearts are as red earth and pouring rain: mingled beyond parting.” This verse from Kurunthogai, translated by A.K. Ramanujan, beautifully encapsulates their love.

# Natasa Stankovic

## Looks Her Sexiest Best In White Outfit After Returning To Mumbai

Natasa Stankovic is currently enjoying some quality time in India. On Thursday afternoon, the actress took to her Instagram handle and dropped a couple of pictures which are now setting fire online. In these latest clicks, Natasa was seen flaunting her curves in a white thigh-high slit gown which had feathers all over. She opted for matching heels, minimal accessories and left her tresses open. Needless to say, the actress looked prettiest as always. Soon after the photos were shared online, fans rushed to the comments section to compliment the actress. While one of the users called her “hottest”, another wrote, “You are gorgeous”. Several others also dropped fire emojis in the comments section. Check it out here:

Natasa Stankovi, who lives in Serbia after her separation with cricketer Hardik Pandya, returned to Mumbai earlier this week with their son, Agastya. On Wednesday too, Natasa was snapped by the paparazzi as she stepped out for dinner with her friends. She looked effortlessly chic in a black strappy, pleated long dress. Natasa



Stankovi, who lives in Serbia after her separation with cricketer Hardik Pandya, returned to Mumbai earlier this week with their son, Agastya. On Wednesday too, Natasa was snapped by the paparazzi as she stepped out for dinner with her friends. She looked effortlessly chic in a black strappy, pleated long dress.

Natasa and Hardik, who tied the knot in May 2020 and renewed their wedding vows according to the Hindu and Christian rituals in February 2023, confirmed their separation in July 2024. They

issued a joint statement and mentioned that it was a “tough decision” for both of them and added that they will continue to co-parent their son, Agastya. Later, a report by Times Now claimed that Natasa and Hardik parted ways because the cricketer was “too full of himself”. “He was too flamboyant for her, too full of himself. Natasa could not handle it anymore. She realised that there was a major gap between how they were as people. She tried to match it up to him but it made her feel uncomfortable. This was a never-ending process so it became tiring after a while. Natasa was not able to keep pace hence she decided to take a step back,” a source cited by the portal claimed.

